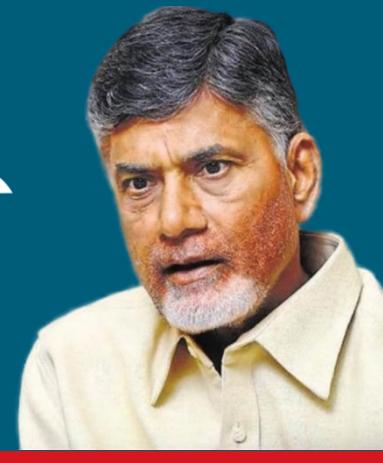




राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

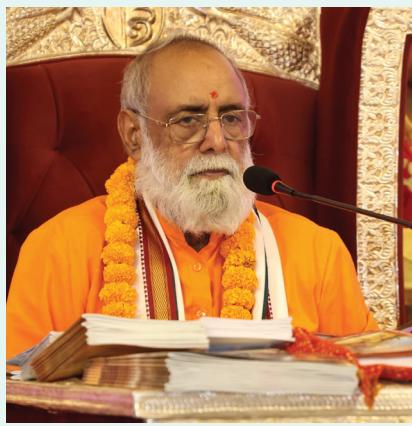
भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक



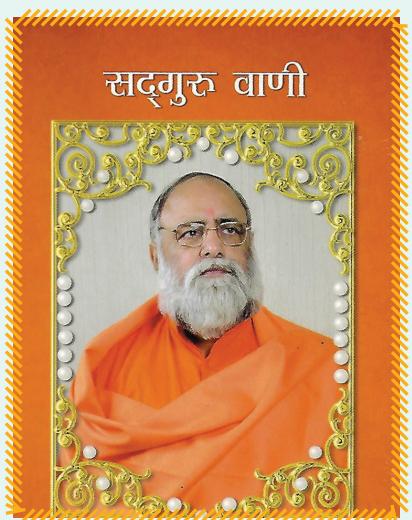
भारत के मुख्यमंत्रियों...

सोमवार, 25 अगस्त 2025 ● वर्ष 7 ● अंक 05 ● मूल्य: 5 रुपए



पूज्य गुरुदेव जी पाठ देकर कहते हैं कि आप विश्वास न करें, पाठ करें। गुरुदेव जी बताते थे कि हर रोग का इलाज हमारी संस्कृति में हजारों साल से ही उपलब्ध है।

पेज-10-11



सद्गुरु वाणी

दिव्य पाठ प्रमुकृपा का वह आलोक है जिसे करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिन तपस्या या साधना की कोई जरूरत नहीं है। यह बड़ा सहज और सरल है।

अपनी आय का जो अंश आप दान के रूप में निकालते हैं वह अंश बीज रूप में पनपता है। यहीं बीज आपके दुखों कष्टों और समस्याओं का समाधान करता है।

प्रार्थनाओं से जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का कभी हल नहीं होता। हम केवल अपनी समस्याओं से भगाने के लिए प्रवर्चनों का सहारा लेते हैं।

अमेरिका का दोहरा चेहरा भारत पर सख्ती



चीन पर चुप्पी



@ भारतश्री ब्लूरो

अमेरिका और भारत के रिश्ते हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे अहम कूटनीतिक साझेदारी के रूप में देखे जाते रहे हैं। रक्षा, तकनीक, व्यापार और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढांचे में दोनों देश एक-दूसरे के अहम सहयोगी हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हालिया बयान ने रिश्तों में नई तलची ला दी है। उन्होंने साफ़-साफ़ मान लिया कि भारत पर लगाए गए सेंकेंडरी टैरिफ़ का मकसद रूस पर दबाव बनाना है। यह बयान न केवल अमेरिका की रणनीति को उजागर करता है बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या वॉशिंगटन वास्तव में भारत के साथ भरोसेमंद साझेदारी चाहता है या फिर उसे केवल अपने भू-राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है।

जेडी वेंस का बड़ा खुलासा

रविवार को एनबीसी न्यूज के कार्यक्रम मीट द प्रेस में इंटरव्यू देते हुए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर यूक्रेन में बमबारी रोकने का दबाव बनाने के लिए भारत पर “आक्रामक आर्थिक दबाव” डाला है। उनके मुताबिक, भारत पर लगाए गए सेंकेंडरी टैरिफ़ का मकसद रूसियों के लिए तेल से होने वाली आमदनी को मुश्किल बनाना है। यानी अमेरिका मानता है कि रूस की अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा तेल है और अगर भारत उस तेल की बड़ी खरीद बंद कर दे तो रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और वह युद्ध रोकने के लिए मजबूर होगा।

भारत पर सख्ती, चीन पर चुप्पी

ट्रंप प्रशासन ने रूस से रियायती तेल की खरीद को लेकर भारत की आलोचना की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देश चीन पर कोई कड़ा बयान या प्रतिवंध नहीं लगाया गया। यहीं दोहरा रवैया भारत में सवाल खड़े कर रहा है। भारत का तर्क है कि सस्ती ऊर्जा खरीदना उसका राष्ट्रीय हित है और यह वैश्विक बाजार के लिए भी फायदेमंद है। वास्तव में रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदकर भारत ने घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर रखीं और इससे पूरी दुनिया

रणनीतिक मजबूरी भी है। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिवंध लगाने के बाद अपनी सप्लाई रोक दी। रूस ने भारत को रियायती दाम पर तेल बेचना शुरू किया। इस सौदे से भारत को ऊर्जा सुरक्षा मिली और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता आई। भारत मानता है कि सस्ती ऊर्जा न केवल उसके नागरिकों बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभकारी है।

अमेरिकी दबाव के सामने भारतीय स्वाभिमान

अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत अपने बाजारों में अमेरिकी उत्पादों को ज्यादा जगह दे, रक्षा सौदे बढ़ाए और गैर-टैरिफ़ बाधाओं को हटाए। अप्रैल में जयपुर में भाषण देते हुए वेंस ने खुद भारत से यहीं अपील की थी लेकिन जब उसी अमेरिका की ओर से भारत के खिलाफ़ “सेंकेंडरी टैरिफ़” जैसी कठोर नीति अपनाई जाती है, तो यह रिश्तों में भरोसे की कमी को दिखाता है। भारत यह सवाल भी उठाता है कि अगर साझेदारी “ब्रावरी” की है तो दबाव डालने की ज़रूरत क्यों?

चीन की चुप्पी क्यों?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला चीन क्यों अमेरिकी निशाने पर नहीं है? क्या अमेरिका चीन से टकराव नहीं चाहता? क्या भारत को “आसान लक्ष्य” समझा गया? या फिर वॉशिंगटन भारत को सिर्फ़ अपने रणनीतिक एजेंटों का हिस्सा बनाना चाहता है? यह असंतुलित रवैया भारत में संदेह को और गहरा कर देता है।

भारत और अमेरिका दोनों ही इस सदी को “इंडो-पैसिफिक साझेदारी” के रूप में देखने की बात करते रहे हैं। तकनीकी सहयोग, रक्षा, क्वाड जैसे मंचों पर दोनों देशों का मेलजोल बढ़ा है। लेकिन अगर अमेरिका भारत को केवल अपने भू-राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करेगा और उसकी आर्थिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगा, तो रिश्तों में खटास और बढ़ सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का यह बयान भारत-अमेरिका रिश्तों की हकीकत को सामने लाता है। दोस्ती और साझेदारी की बातें भले ऊंचे मंचों से हों, लेकिन जब दबाव और टैरिफ़ जैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो भरोसे की नींव कमज़ोर होती है।



ORDER ALL TYPES OF :

- POOJA SAMAGRI,
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND PRATIMA.



NOW GET AT YOUR HOME ON
MNDIVINE.COM



ORDER NOW



<https://mndivine.com/>

HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)



SSC भर्ती घोटाले पर सियासी संग्राम

रामलीला मैदान से संसद तक गूँज

@ सुमित शुक्ला

दि

ल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान हमेशा से आंदोलनों और लोकतांत्रिक आवाजों का गवाह रहा है। रविवार रात एक बार फिर यही मैदान चर्चा का केंद्र बन गया, जब स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) भर्ती परीक्षा की गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे छात्र-आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई ने विवाद खड़ा कर दिया। लाठीचार्ज और हिंसा की खबरों ने न सिर्फ छात्रों को हिला दिया, बल्कि विषयी दलों को भी केंद्र सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। सोमवार सुबह जब छात्रों और अभिभावकों ने मैदान में प्रवेश की कोशिश की तो वहां भारी पुलिस बल तैनात दिखा। बैरिकेटिंग और बंद रास्तों ने प्रदर्शन को पूरी तरह टप कर दिया। लेकिन इस खामोशी के बीच सियासी हलचल तेज हो गई।

कई महीनों से युवा कर रहे हैं प्रोटेस्ट

पिछले कई महीनों से देशभर के युवा SSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक की शिकायत कर रहे हैं। बेरोजगारी की मार झेल रही थी पीढ़ी साफ़-सुधरी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रही थी। छात्रों का कहना है कि जब उनकी मेहनत और भविष्य दोनों दांव पर लगे हैं, तो सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। रात को हुई घटना ने माहौल गरमा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दर्जनों छात्रों-शिक्षकों को हिंसा से लिया। मीडिया को मैदान में कवरेज से रोकने की भी बात सामने आई। दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि “तथा समय सीमा के बाद भी प्रदर्शनकारी मैदान में डटे रहे थे, इसलिए 44 लोगों को हिंसा से लिया गया।” लेकिन छात्रों, अभिभावकों और कई शिक्षकों का आरोप है कि यह सिर्फ़ “बल प्रयोग” था और असल मक्क्षण युवाओं की आवाज़ दबाना था।

केजरीवाल का सीधा हमला

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अर्थविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने एक्स (पूर्व ट्रिवटर) पर लिखा, “बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए। SSC की गड़बड़ियों पर महीनों से छात्र इंसाफ़ की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी आवाज़ सुनने के बजाय रात में उन पर लाठियाँ बरसाई गईं। मीडिया को रोका गया। लोकतंत्र ही नहीं, पूरे सिस्टम का मज़ाक बना दिया गया है।”

लोकतंत्र बनाने दमन-तंत्र?

विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय उनकी आवाज़ दबा रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह यह आंदोलन अब सियासी मुद्दा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या लोकतांत्रिक भारत में युवाओं के सवाल उठाने पर लाठियाँ ही जबाब होंगी? दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, केवल तथा समय सीमा खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों को हिंसा से लिया

**कांग्रेस भी उत्तरी मैदान में**

सिर्फ AAP ही नहीं, कांग्रेस और उसके छात्र संगठन NSUI ने भी सरकार पर करारा वार किया। NSUI ने एक्स पर लिखा: “साफ़-सुधरी SSC भर्ती की मांग करने पर मोदी सरकार ने छात्रों को लाठियों से पिटवाया। जो बेरोजगारी दूर नहीं कर सके, अब युवा आवाज़ दबाने में जुटे हैं। सुन लो नरेंद्र मोदी युवाओं का ठक छीन नहीं पाओगे।” इसी मुद्दे पर बिहार के मुंगेर में राहुल गांधी ने प्रतियोगी छात्रों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि देशभर में युवा पेपर लीक और भर्ती घोटालों का शिकायत ले रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार युपयाप तमाशा देख रही है। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है और “युवा की आवाज़ दबेगी नहीं।”



गया। लेकिन छात्रों और विपक्ष का कहना है कि पुलिस बयान सच को छिपाने की कोशिश है।

लाठी-लीला कातंज

AAP नेता मनीष सिसोदिया ने इस घटना पर व्यंग्य कसते हुए लिखा कि भाजपा ने रामलीला मैदान को “लाठी-लीला” बना दिया। उनका आरोप था कि मोदी

सरकार रोजगार देने में सबसे पीछे है लेकिन युवाओं पर लाठियाँ बरसाने में नंबर वन है। वहीं, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार सवाल पूछने वाले छात्रों को सुनने की बजाय उनकी आवाज़ कुचल रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र नहीं बल्कि “दमन-तंत्र” करार दिया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज

ने रात दो बजे पुलिस थाने के बाहर खड़े छात्रों-शिक्षकों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि यह अन्याय बर्दाशत नहीं किया जाएगा।

छात्रों का दर्द और अभिभावकों की चिंता

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि SSC जैसी संस्था से अगर पारदर्शिता गायब हो जाएगी तो प्रतियोगी परीक्षाओं पर से भरोसा ही खत्म हो जाएगा। “हम दिन-रात मेहनत करते हैं, सालों तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा ही फर्जी हो, पेपर लीक हो जाए तो भविष्य अंधकारमय हो जाता है,” एक छात्र ने कहा। अभिभावकों का गुस्सा भी साफ़ दिखा। उनका कहना था कि बच्चे सङ्को फर्जी साफ़ दिखा। उनका कहना था कि भाजपा सरकार का जवाब सिर्फ़ लाठीचार्ज है।

बेरोजगारी और भर्ती घोटाल

यह आंदोलन सिर्फ SSC भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं है। हाल के वर्षों में कई राज्यों और केंद्र स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और भर्ती घोटाले सामने आए हैं। इससे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार ने बेरोजगारी की समस्या हल करने की बजाय छात्रों को “सङ्केत तंत्र” पहुँचाने का काम किया है। रामलीला मैदान की यह घटना सिर्फ़ एक आंदोलन की तस्वीर नहीं, बल्कि उस बेचैनी की आवाज़ है जो देश का युवा महसूस कर रहा है। बेरोजगारी, भर्ती घोटाले और पारदर्शिता की कमी ने छात्रों को सङ्को पर लग दिया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र नहीं बल्कि “दमन-तंत्र” करार दिया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज़ की यह घटना सिर्फ़ एक आंदोलन की तस्वीर नहीं, बल्कि उसे लेकिन विपक्ष और छात्रों के आरोप अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं।



ग्रेटर नोएडा की निककी भाटी मौत मामला

दहेज हत्या, हादसा या कुछ और?

@ मनीष पांडेय

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गाँव में 27 साल की निककी भाटी की मौत ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। 21 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे जो कुछ भी हुआ, वह अब तक एक पहेली बना हुआ है। पहले इसे सिलेंडर विस्फोट से जुड़ा हादसा बताया गया, लेकिन अब सामने आ रही तस्वीरें और वीडियो कई नए सवाल खड़े कर रहे हैं निककी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर अंतिम संस्कार का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो ने पुलिस की जांच की दिशा बदल दी। अब दहेज हत्या का मामला दर्ज हो चुका है और निककी के पति विपिन भाटी समेत पूरे परिवार पर गंभीर आरोप लगे हैं।

निककी की बहन कंचन के आरोप

इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी निककी की छोटी बहन कंचन मानी जा रही है। कंचन ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाता था और पति विपिन ने जलाकर उसकी हत्या कर दी। कंचन ने दावा किया कि विपिन का कई अन्य महिलाओं से संबंध था, जिनकी चैट उसने सोशल मीडिया पर शेयर भी की। उनका कहना है कि विपिन की हरकतों का विरोध करने पर निककी को प्रताड़ित किया जाता था यही नहीं, कंचन का यह भी आरोप है कि विपिन और उसके घरवालों ने निककी को जिंदा जलाया और फिर कहानी बदलने के लिए सिलेंडर विस्फोट का बहाना बना दिया।

अस्पताल और विस्फोट की कहानी

घटना के बाद निककी को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के रिकार्ड में बताया गया कि निककी सिलेंडर विस्फोट में झुलसी थी। अस्पताल के प्रवक्ता ने



कहा कि जब मरीज को भर्ती कराया गया तो यही जानकारी दी गई थी विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र का कहना है कि अस्पताल में निककी ने खुद उन्हें सिलेंडर फटने की बात बताई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सच था या किसी दबाव में निककी ने ऐसा कहा? कंचन और मायकेवालों का आरोप है कि यह सब झूठ है और सिलेंडर विस्फोट का ड्रामा रखाकर हत्या को हादसा बताने की कोशिश की गई।

वीडियो ने बदल दिया मामला

जांच को और उलझा देने वाला पहलु सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो हैं। एक वीडियो में अंतिम संस्कार के समय विपिन के पिता नजर आ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के और जल्दबाजी में निककी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक अन्य वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जो निककी से कह रही है – “ये तूने क्या कर लिया बहन?”। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या यह आवाज कंचन की है। अगर हाँ, तो सवाल उठेगा कि उस

वक्त कंचन मौके पर मौजूद थीं या नहीं। यही नहीं, एक और वीडियो में निककी की सास उसे पति विपिन से बचाने की कोशिश करती दिख रही है। पुलिस यह जांच कर रही है कि यह वीडियो घटना से पहले का है या बाद का।

CCTV फुटेज की मांग

निककी के परिवार का कहना है कि घर के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस को उनकी फुटेज निकालनी चाहिए। उनका दावा है कि इन फुटेज से सच सामने आ जाएगा। चैटरे भाई ने कहा कि अगर यह हादसा था तो CCTV फुटेज क्यों छुपाई जा रही है? उन्होंने सिलेंडर विस्फोट की थ्योरी को पूरी तरह झूठ बताया और कहा कि यह कहानी गढ़ी गई है ताकि हत्या को छिपाया जा सके।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने अब तक निककी के पति विपिन, सास-ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। कासना कोतवाली पुलिस लगातार दोनों परिवारों के 10-12 गवाहों से बयान

दर्ज कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कंचन के बयान बहुत अहम हैं। इसलिए उन्हें दोबारा बुलाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस यह भी जानना चाहती है कि सोशल मीडिया पर डाले गए चैट और वीडियो कितने सटीक हैं।

परिवार बनाम परिवार

इस घटना ने दो परिवारों को आपने-सामने खड़ा कर दिया है विपिन का परिवार कह रहा है कि यह एक हादसा था और निककी ने खुद को आग लगाई निककी का मायका पक्ष कह रहा है कि यह साफ-साफ हत्या है और उसे दहेज के लिए जिंदा जलाया गया दोनों तरफ से अलग-अलग बयान आने से पुलिस के लिए सच्चाई तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर बहस

निककी की मौत का मामला सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। लोग इसे महिला उत्पीड़न और दहेज हत्या का मामला बता रहे हैं। कई जगह #JusticeForNikki-ki हैशटैग के साथ पोस्ट हो रहे हैं। कंचन द्वारा शेयर की गई चैट और वीडियो ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। वहीं, कुछ लोग विपिन और उसके परिवार के समर्थन में भी पोस्ट कर रहे हैं और इसे परिवारिक विवाद बता रहे हैं।

दहेज हत्या का बदला खतरा

यह मामला सिर्फ निककी की मौत तक सीमित नहीं है। यह समाज के उस दर्दनाक सच को सामने लाता है जहां आज भी दहेज की वजह से बेटियों की जान जाती है। दहेज हत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे मामलों में अक्सर सच सामने आने में देर लग जाती है। अब सबकी निगहें पुलिस जांच पर टिकी हैं। क्या सच में निककी ने खुद को जलाया?

कुत्तों के हक्क में सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा रुख़

कुत्तों के हक्क में सुप्रीम कोर्ट ने कानून का अदेश दिया है। कुछ लोग उन्हें प्यार करते हैं, तो कुछ डरते हैं। भारत में आवारा कुत्तों की समस्या बढ़ी है। हर साल लाखों लोग कुत्तों के काटने से घायल होते हैं। लेकिन कुत्तों के अधिकार भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर बड़े फैसले लिए हैं। अगस्त 2025 में दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन लोगों के विरोध के बाद कोर्ट ने अपना फैसला बदला। अब कुत्तों को नसबंदी और टीका लगाकर वापस छोड़ने का आदेश है। यह फैसला जानवरों के कल्याण और लोगों की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखता है। क्या यह सही है? सोचने वाली बात है। एक तरफ बच्चे और बूढ़े सुरक्षित रहें, दूसरी तरफ कुत्ते भी जी सकें। भारत में ३ करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। समस्या हल करने के लिए क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या कहता है? कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को मारना या हमेशा बंद रखना गलत है। लेकिन अगर वे रेबीज़ से संक्रमित हैं या आक्रामक हैं, तो उन्हें अलग रखा जाए। बाकी कुत्तों को पकड़ो, नसबंदी करो, टीका लगाओ और वापस उसी जगह छोड़ दो। यह फैसला 22 अगस्त 2025 को आया। इससे पहले 11 अगस्त को कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश दिया था। वजह थी कि कुत्तों के काटने की बढ़ती शिकायतें दिल्ली में हर साल लाखों मामले आते हैं। लेकिन डॉग लवर्स ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुत्ते भी जीव हैं, उन्हें सड़क से हटाना कूरता है। कोर्ट ने उनकी बात सुनी और आदेश बदला। अब सभी राज्यों को नोटिस दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की बात है। यह दिखाता है कि कोर्ट संतुलन रखना चाहता है। लेकिन क्या यह व्यावहारिक है? नगर निगम के पास इतने संसाधन हैं? सोचिए, अगर कुत्ते वापस आ गए तो समस्या वैसी ही रहेगी। फिर भी, यह क्रदम जानवरों के प्रति दिया दिखाता है। भारत में जानवरों की कूरता रोकने का कानून 1960 से है। कोर्ट ने कई बार कहा कि कुत्तों को खिलाना अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी भी। कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट बहुत नरम है। बच्चे स्कूल जाते हुए डरते हैं। बुजुर्ग पार्क में नहीं घूम सकते। लेकिन डॉग लवर्स कहते हैं कि कुत्ते हमारी गलती से आवारा हुए। हम कचरा फैलाते हैं, वे भूखे रहते हैं। दोनों पक्ष सही हैं। समाधान बीच का रास्ता है। कोर्ट ने यही किया। अब देखना है कि ज़मीन पर क्या होता है। दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। अगर सभी को टीका लगाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार को सोचना पड़ेगा।

डॉग लवर्स से पैसे गांगने की असली वजह

सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को पैसे देने को क्यों कहा? यह सवाल कई लोगों के मन में है। 22 अगस्त 2025 के फैसले में कोर्ट ने कहा कि जो डॉग लवर्स और एनजीओ कोर्ट आए हैं, वे पैसे जमा कराएँ। हर व्यक्ति 25000 रुपये और हर एनजीओ 2 लाख रुपये। यह पैसा कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा होगा। वजह क्या है? कोर्ट ने कहा कि यह पैसा आवारा कुत्तों के लिए सुविधाएँ बनाने में लगेगा। जैसे शेल्टर होम, दवाईयाँ और देखभाल। डॉग लवर्स कुत्तों के हक्क की बात करते हैं, तो जिम्मेदारी भी ले। यह कोई सज्जा नहीं, बल्कि योगदान है। कोर्ट ने साफ़ कहा कि अगर आप कुत्तों को बचाना चाहते हों, तो मदद करो।



इससे पहले कोर्ट ने सभी कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश दिया था। लेकिन विरोध हुआ। मेनका गांधी जैसी नेता ने कहा कि कुत्तों को हमेशा बंद रखना गलत है। जॉन अब्राहम ने भी समर्थन किया। लोगों ने पेटिशन दाखिल किया। कोर्ट ने सुना और आदेश बदला। लेकिन साथ में पैसे का प्रावधान रखा। क्यों? क्योंकि शेल्टर बनाने में खर्च लगता है। सरकार अकेले नहीं कर सकती। डॉग लवर्स लाखों की संख्या में हैं। अगर वे योगदान दें, तो समस्या हल हो सकती है। लेकिन क्या यह सही है? कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट क्यों पैसे मांग रहा है। यह तो सरकार का काम है। लेकिन सोचिए, डॉग लवर्स कुत्तों को खिलाते हैं, लेकिन जब काटने की घटना होती है, तो जिम्मेदारी कौन ले? कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना न दें। अलग जगह बनाएँ। यह विचार-उत्तेजक है। अगर आप प्यार करते हों, तो पूरी जिम्मेदारी लो। अपनाएँ या शेल्टर में रखें। भारत में 3.5 लाख डॉग लवर्स ने पेटिशन साइन की। अगर हर कोई थोड़ा दे, तो बड़ा कर्फ़ु पड़ेगा। लेकिन क्या सभी तैयार हैं? कुछ एनजीओ ने विरोध किया। कहते हैं कि पैसा देना अनुचित है। लेकिन कोर्ट का तर्क है कि योगदान से ही बदलाव आएगा। यह फैसला नया है। देखना है कि कितने लोग पैसे जमा करते हैं। एक हफ्ते का समय दिया गया है। अगर नहीं दिया, तो क्या होगा? कोर्ट ने नहीं बताया। लेकिन यह दिखाता है कि जानवरों के अधिकार के साथ जिम्मेदारी जुड़ी है। दोनों तरफ़ सोचें।

भारत में आवारा कुत्तों की समस्या और कोर्ट का नियायिका

भारत में आवारा कुत्ते बड़ी समस्या हैं। दिल्ली में अकेले 10 लाख हैं। पूरे देश में 6 करोड़ से ज्यादा। हर साल 30 लाख लोग काटे जाते हैं। रेबीज़ से 20000 मौतें होती हैं। बच्चे, बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित। लेकिन कुत्ते क्यों आक्रामक होते हैं? भूख, बीमारी या डर से। हम कचरा फैलाते हैं, वे खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार

फैसले दिए। 2009 से कह रहा है कि नसबंदी और टीका लगाकर वापस छोड़ो। मारना गलत है। 2014 में कहा कि कुत्तों को खिलाना अधिकार है। लेकिन अब 2025 में बदला। सार्वजनिक जगहों पर खाना न दें। आक्रामक कुत्तों को अलग रखो। कोर्ट का स्टैंड संतुलित है। एक तरफ़ जानवरों की कूरता रोकना, दूसरी तरफ़ लोगों की सुरक्षा। लेकिन अमल कैसे हो? नगर निगम के पास पैसे कम हैं। एनजीओ मदद करते हैं, लेकिन काफ़ी नहीं। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस दिया। राष्ट्रीय नीति बने। क्या यह काम करेगा? सोचिए, अगर कुत्ते वापस छोड़ दिए, तो काटने की घटनाएँ कम होंगी? टीका लगाने से रेबीज़ रुकेगा। लेकिन आक्रामक व्यवहार कैसे पता चले? कौन तय करेगा? मेनका गांधी ने कहा कि यह फैसला अच्छा है, लेकिन अमल सही हो। राहुल गांधी ने भी स्वागत किया। लेकिन विरोधी कहते हैं कि कोर्ट लोगों की पीड़ियाँ नहीं समझता। सोशल मीडिया पर बहस है। कुछ कहते हैं कि कुत्तों के लोगी मजबूत है। कशमीर के पीड़ियों से ज्यादा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोर्ट कानून से बंधा है। जानवरों का कानून 1960 कहता है कि कूरता न हो। लेकिन लोगों की सुरक्षा भी ज़रूरी। दोनों को बैलेस करना मुश्किल। क्या समाधान है? ज्यादा शेल्टर बनाएँ। लोगों को जागरूक करें। कुत्तों को अपनाने को प्रोत्साहन दें। अगर डॉग लवर्स अपनाएँ, तो समस्या कम हो। लेकिन कितने तैयार? 3.5 लाख पेटिशन साइन करने वाले अगर 3 कुत्ते अपनाएँ, तो सारी समस्या हल हो। लेकिन हकीकत अलग है। कोर्ट का फैसला विचार करने लायक है। क्या हम जिम्मेदार हैं? या सिर्फ़ बातें करते हैं?

दुनिया के दूसरे देशों में कुत्तों के कानून क्या हैं?

दुनिया में कुत्तों के कानून अलग-अलग हैं। कुछ देशों में आवारा कुत्ते बिलकुल नहीं। जैसे नीदरलैंड्स। वहाँ सभी कुत्तों की नसबंदी होती है। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी। कोई मारता नहीं। स्विट्जरलैंड में जानवरों के अधिकार

मजबूत। सामाजिक जानवरों को अकेला नहीं रख सकते। जर्मनी में प्रजनन पर सख्त कानून। कुत्तों को चोट पहुँचाना जुर्म। ब्रिटेन में माइक्रोचिप लगाना ज़रूरी। आवारा कुत्तों को 7 दिन पकड़ते हैं, फिर अपनाने देते हैं। अमेरिका में राज्य अनुसार कानून। कूरता पर जेल। लेकिन कुछ जगहों पर गैस चैंबर इस्तेमाल होता था, अब कम। तुर्की में हाल ही कानून आया। आवारा कुत्तों को पकड़ो, नसबंदी करो, अपनाने दो। अगर नहीं, तो मार दो। लेकिन विरोध हुआ। रोमानिया में पहले मारते थे, अब नसबंदी। यूरोप में १० करोड़ आवारा कुत्ते-बिल्लियाँ। लेकिन कानून सख्त। चीन में खराब। कुत्ते खाने के त्योहार होते हैं। भारत जैसा टीएनवीआर (ट्रैप-न्यूट्र-वैक्सीनेट-रिटर्न) कई देशों में है। लेकिन अमल बेहतर। क्या हम सीख सकते हैं? नीदरलैंड्स ने बिना मारकर समस्या हल की। सख्त रजिस्ट्रेशन से। स्विट्जरलैंड में जानवरों को प्रवार जैसा मानते हैं। लेकिन भारत में जनसंख्या ज्यादा। संसाधन कम। अगर हम सख्त कानून बनाएँ, तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जानवरों के अधिकार भी रखें। कुछ देशों में अपनाने पर टैक्स छूट। क्या भारत में ऐसा हो? सोचने वाली बात। एक तरफ़ सुरक्षा, दूसरी तरफ़ दया। बैलेस ज़रूरी। दुनिया से सीखकर हम बेहतर कर सकते हैं।

संतुलन की ज़रूरत

कुत्तों की समस्या आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कदम उठाया। लेकिन अमल पर निर्भर। डॉग लवर्स पैसे दें, जिम्मेदारी लें। सरकार शेल्टर बनाएँ। लोग जागरूक हों। कुत्तों को अपनाएँ। दुनिया के देशों से सीखें। नीदरलैंड्स जैसा मॉडल अपनाएँ। लेकिन भारत की हकीकत अलग। क्या हम तैयार हैं? सोचिए। अगर सभी मिलकर काम करें, तो समस्या हल हो सकती है। जानवर और इंसान साथ रह सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी सबकी। यह फैसला हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सिर्फ़ विरोध करते रहेंगे, या समाधान निकालेंगे? समय बताएंगा।

आवारा कुर्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

भारत का सुप्रीम कोर्ट भी बेवारा कई मामलों में लावार हो जाता है ना याहते हुए भी उसे इस प्रकार के लोगों के सामने झुकना पड़ जाता है। अभी आपने देखा होगा की सुप्रीम कोर्ट ने कुर्तों के संबंध में एक निर्णय दिया था। वह निर्णय यद्यपि कम कठोर था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। मैं तो 50 वर्षों से लगातार बोलते रहा हूं कि पशुओं को कोई गौलिक अधिकार नहीं होता है। यदि पशुओं की संख्या बढ़ जाए तो उन्हें मारने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मांसाहर श्रद्धा नहीं है लेकिन आप मांसाहर को रोक भी नहीं सकते। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी तरह यदि कोई अपने मंदिरों में बलि घड़ाता है उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मंदिर प्रशासन का काम है कि वह अनुमति दे या ना दे। इसी तरह कुर्तों को भी यदि उनकी संख्या अधिक हो जाए तो सीधा मार देना चाहिए। उसके लिए कोई नाटक बाजी करने की जरूरत नहीं है। यह जीव दया सिद्धांत का नाटक करने वाले लोग पूरी तरह गलत हैं। आप जरा सोचिए कि हम विदेशों से अनेक वस्तुओं का आयात कर रहे हैं और हम अपने संसाधन इस प्रकार के आवारा कुर्तों को खिलाते रहे यह कठन तक अवित है। मैं तो इस बात के भी यक्ष में नहीं था कि कुर्तों को गोली मार दी जाए मैं तो इस बात के यक्ष में था कि यदि इस प्रकार के कुर्ते बढ़ जाते हैं उन्हें सब को इकट्ठा करके करंट दे देना चाहिए। किसी प्रकार की कोई मानवता सरकार को नहीं दिखानी चाहिए। फिर भी जब मेनका गांधी और राहुल गांधी प्रियंका गांधी ऐसे ऐसे आलू फालत लोग कूद पड़े और अनेक पशु प्रेमी भी हल्ला करने लगे तब बेवारे सुप्रीम कोर्ट को कल अपने आदेश में थोड़ा सा सुधार करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात करूँ कर बहुत अच्छा कार्य किया है की जो भी पशु प्रेमी या संस्थाएं व्यायालय में आई है उन सबको एक सप्ताह के अंदर 15000 से 200000 तक जमा करना पड़ेगा जिससे पशुओं पर होने वाले खर्च की आंशिक भरपाई हो सके। मैं यह समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बेवारा बदनामी से डरता है यह अलग बात है लेकिन समझता तो सब कुछ है यह बात भी सच है।

बजरंग मुनि

जुबानी तीर

“

निककी भाटी की मौत सिर्फ़ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में दहेज प्रथा और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता साफ़ दिखाई देती है। जब तक ऐसी घटनाओं में सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक बेटियां दहेज की आग में जलती रहेंगी।

प्रियंका गांधी वाड़ा
(कांग्रेस महासचिव)

“



ग्रेटर नोएडा की इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। यूपी में महिलाओं पर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। दहेज हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार सिर्फ़ कागजों में सुरक्षा के दावे कर रही है। निककी को न्याय तभी मिलेगा जब दोषियों को उदाहरण बनाकर सख्त सज्जा दी जाए।

अखिलेश यादव
(पूर्व मुख्यमंत्री, सपा अध्यक्ष)

“

यह बेहद दुखद घटना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्क्रिया और तेज़ जांच हो। दोषियों को किसी भी हाल में बख्खा नहीं जाएगा, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों। हमारी सरकार बेटियों की सुरक्षा और न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

स्वतंत्र देव सिंह (भाजपा नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष)



लोकतंत्र की असली परीक्षा

@ अनुराग पाठक

भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक प्रयोग है। मगर यह तथ्य केवल संख्या में ही है नहीं वर्तमान नहीं दिलाता, असली सवाल है कि क्या यहां हर नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग समान रूप से कर पा रहा है। क्या वोट केवल शहरी मध्यवर्ग की आदत भर बनकर रह गया है या यह उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा है जिसके लिए संविधान ने इसे सबसे बड़ा अधिकार बताया था? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए राहुल की यात्रा एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की ताकत केवल चुनावी नीतियों में नहीं, बल्कि वोट डालने की प्रक्रिया में छिपी होती है।

भारतीय समाज की सच्चाई यही है कि बड़ी आबादी अब भी वोट देने से वंचित रह जाती है। कभी भौगोलिक कठिनाइयाँ आड़े आती हैं, कभी वोटर लिस्ट से नाम गायब होता है, तो कभी सामाजिक दबाव लोगों को मतदान से रोक देता है। महिलाएँ आज भी कई क्षेत्रों में परिवार की अनुमति के बिना वोट नहीं डाल पातीं। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में बूथ तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में लोकतंत्र केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। राहुल की यात्रा इसी ठहराव पर चोट करती है और जनता को याद दिलाती है कि वोट केवल कागज का अधिकार नहीं, बल्कि अस्तित्व की पुष्टि है।

यह बात माननी होगी कि भारतीय राजनीति में इस तरह की यात्राएँ नई नहीं हैं। समय-समय पर नेता पदयात्राएँ करते रहे हैं। अक्सर इन पर यह आरोप भी लगता है कि यह सब सत्ता की राजनीति के लिए होता है, असल बदलाव के लिए नहीं। राहुल की यात्रा भी इस आलोचना से मुक्त नहीं। राजनीतिक विपक्ष इसे महज 'इंवेंट मैनेजमेंट' करार देगा। लेकिन सवाल यह है कि यदि इस बहाने भी वोट पर चर्चा शुरू होती है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है और लोग जागरूक होते हैं, तो क्या हमें इसे सिर्फ़ दिखावा मानकर खारिज कर देना चाहिए? लोकतंत्र में प्रतीक भी उतने ही जरूरी होते हैं जिनके लिए नीतियाँ।

फिर भी यह उम्मीद करना भोलेपन से कम नहीं कि केवल यात्राओं से ही समस्या का समाधान हो जाएगा। वोटिंग प्रतिशत घटने की असली वजहें गहरी हैं। एक बड़ा तबका यह मान बैठा है कि वोट देने से कुछ बदलता नहीं। सरकारें आती-जाती हैं, पर उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। यह राजनीतिक व्यवस्था पर अविश्वास है, जिसे केवल नारेबाजी से नहीं तोड़ा जा सकता। इसके लिए ठोस नीतिगत सुधार चाहिए—मतदाता सूची की पारदर्शिता, बूथों तक आसान पहुंच, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएँ,

और सबसे बढ़कर ऐसा राजनीतिक माहौल जिसमें जनता को लगे कि उसका वोट वाकई असर डालता है।

यात्रा का दूसरा पहलू है युवाओं को जोड़ना। यह सही है कि पहली बार वोट देने वाले मतदाता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। मगर यह भी उतना ही सच है कि वे राजनीति से सबसे अधिक निराश भी हैं। उन्हें केवल जागरूक करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि राजनीति उनके सपनों और आकांक्षाओं की भाषा बोल सकती है। यदि राहुल की यात्रा यह भरोसा जगा पाती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यह केवल भाषणों और तस्वीरों में सिमट गई तो जनता इसे एक और असफल प्रयोग मानकर भूल जाएगी।

लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। जब सरकारें बूथों तक पहुंच आसान नहीं बना पातीं, वोटर लिस्ट सही नहीं रख पातीं, या मतदान को पारदर्शी और निष्क्रिय नहीं बना पातीं, तब यात्राएँ केवल प्रतीक बनकर रह जाती हैं। विपक्ष के लिए यह मौका है कि वह इन खामियों की ओर ध्यान दिलाएँ और जनता को संगठित करे। राहुल की यात्रा यदि इस भूमिका को निभा पाती है तो यह केवल एक राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि लोकतंत्रिक सुधार की दिशा में सार्थक पहल कही जाएगी।

सवाल यह भी है कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ लोकतंत्र केवल चुनावी गणित तक सिमटकर रह जाए? यदि हाँ, तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार होगी। राहुल की वोट अधिकार यात्रा हमें यही चेतावनी देती है। यह यात्रा इस मायने में अहम है कि यह मताधिकार को फिर से बहस के केंद्र में लाती है। यह बताती है कि वोट केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह नागरिकता की धोषणा है, यह सत्ता को जवाबदेह बनाने का हथियार है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह जनता को शक्तिशाली बनाता है। लेकिन जब जनता ही अपने अधिकार का प्रयोग करने से पीछे हट जाए, तो यह व्यवस्था खोखली हो जाती है। राहुल की यात्रा इस खोखलेपन को भरने का प्रयास है। अब यह जनता और व्यवस्था दोनों को जिम्मेदारी है कि इसे केवल प्रतीक न बनने दें। यदि वोट के अधिकार की गरिमा बचानी है तो जागरूकता के साथ-साथ ठोस सुधार भी जरूरी हैं।

भारत का लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब हर नागरिक गर्व से कह सके कि उसने वोट डाला है और उसका वोट मायने रखता है। राहुल की यात्रा इस आदर्श की ओर बढ़ने का एक कदम है। लेकिन इसे इतिहास में दर्ज करने के लिए केवल यात्रा काफी नहीं, बल्कि ठोस परिणाम और स्थायी बदलाव चाहिए। यही कसौटी तय करेगी कि यह पहल लोकतंत्र की आत्मा को पुनर्जीवित करने वाली बनी या फिर राजनीति के शोर में गुम हो गई।

याददाश्त को मजबूत करने का आयुर्वेदिक तरीका



@ डॉ महिमा मक्कर

मा नव जीवन में स्मरण शक्ति यानी याददाश्त का महत्व अत्यंत गहरा है। शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत रिश्तों – हर जगह स्मरण शक्ति हमारी सफलता की आधारशिला बनती है। लेकिन आधुनिक जीवनशैली, तनाव, असंतुलित आहार, नींद की कमी और तकनीक पर बढ़ती निर्भरता ने हमारी याददाश्त को कमजोर करना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में आयुर्वेद, जो भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, हमें जीवनशैली और प्राकृतिक उपायों के माध्यम से स्मरण शक्ति को मजबूत करने के आसान और प्रभावी मार्ग बताता है। आइए जानें कि याददाश्त को तेज और मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद किन उपायों और नुस्खों की सलाह देता है।

1. याददाश्त और आयुर्वेद का संबंध

आयुर्वेद के अनुसार हमारी स्मरण शक्ति का सीधा संबंध मस्तिष्क के तीन प्रमुख कार्यों से है –

धारण शक्ति (Retention) – सीखी या देखी गई चीज को पकड़ कर रखने की क्षमता।

स्मृति (Recall) – आवश्यकता पड़ने पर उस जानकारी को याद करना।

बुद्धि (Intellect) – सही और गलत का विवेक कर निर्णय लेना।

आयुर्वेदिक ग्रंथों में 'मेद और ओज' को मस्तिष्क और मानसिक शक्ति का आधार बताया गया है। जब यह तत्व संतुलित होते हैं, तो दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है और स्मरण शक्ति प्रखर होती है।

2. सही आहार का महत्व

आयुर्वेद कहता है – "आहार ही औषधि है।" मस्तिष्क को ऊर्जा और पोषण मुख्यतः हमारे भोजन से मिलता है। यदि आहार संतुलित हो तो याददाश्त स्वतः

ही बेहतर होती है।

घी: देसी घी को आयुर्वेद में 'ब्रेन टॉनिक' माना गया है। यह मस्तिष्क की नसों को पोषण देता है और एकाग्रता बढ़ाता है।

बादाम: भीगे हुए बादाम मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं।

अखरोट और अलसी: इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है, जो स्मरण शक्ति को मजबूत करता है।

हरी पत्तेदार सब्जियां और फल: इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं, जो मानसिक थकान को दूर करते हैं।

दूध और शहद: इनका संयोजन दिमाग को ऊर्जा देता है और पढ़ाई या मानसिक कार्यों के दौरान सहायक होता है।

3. आयुर्वेदिक औषधियां और जड़ी-बूटियां

कई जड़ी-बूटियों को आयुर्वेद में 'मेध रसायन' यानी स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली औषधियों के रूप में वर्णित किया गया है।

ब्राट्सी (Bacopa Monnieri): यह मस्तिष्क की नसों को पोषण देती है, तनाव को कम करती है और स्मरण शक्ति को तीव्र बनाती है।

शंखपृष्ठी: यह मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने में कारगर है।

अश्वगंधा: तनाव और चिंता को दूर कर मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाती है।

जटामांसी: नींद को बेहतर बनाती है और स्मरण शक्ति को सुदृढ़ करती है।

यष्टिमधु (मुलेरी): बुद्धि और स्मरण शक्ति को जाग्रत करने में मदद करती है।

इन जड़ी-बूटियों का सेवन पाउडर, घृत (घी में तैयार औषधि) या टेबेलेट/सिरप के रूप में आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से किया जा सकता है।

4. दिनचर्या और जीवनशैली में सुधार

आयुर्वेद केवल दवाओं से नहीं, बल्कि संतुलित जीवनशैली से भी याददाश्त को मजबूत करने की सलाह देता है।

योग और प्राणायाम:

अनुलोम-विलोम और भ्रामी प्राणायाम दिमाग को शांति देते हैं।

मेडिटेशन एकाग्रता और फोकस को बेहतर बनाता है।

पर्याप्त नींद: नींद की कमी याददाश्त को सबसे अधिक प्रभावित करती है। प्रतिदिन 6-8 घंटे की गहरी नींद आवश्यक है।

नियमित दिनचर्या: समय पर भोजन, समय पर सोना और जागना मस्तिष्क को स्थिर और संतुलित रखता है।

डिजिटल डिटॉक्स: लगातार मोबाइल, टीवी और लैपटॉप पर समय बिताने से मस्तिष्क थक जाता है। प्रतिदिन कुछ समय तकनीक से दूर बिताना स्मरण शक्ति को तरोताजा करता है।

5. आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियां

आयुर्वेद में कुछ विशेष उपचार भी बताए गए हैं, जो मस्तिष्क और स्मरण शक्ति पर सीधी प्रभाव डालते हैं।

शिरोधारा: इसमें औषधीय तेल को लगातार मस्तिष्क के मध्य भाग पर डाला जाता है। यह तनाव को दूर कर दिमाग को सक्रिय करता है।

नस्य कर्म: इसमें औषधीय तेल या घी की बूंदें नाक में डाली जाती हैं। यह सीधे मस्तिष्क तक पहुँचकर नसों को पोषण देता है।

अध्ययन (तेल मालिश): पूरे शरीर की मालिश रक्त संचार को बढ़ाती है और दिमाग को शांति देती है।

6. मानसिक व्यायाम

सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है।

पहेलियाँ हल करना

नया विषय पढ़ना

भाषा या संगीत सीखना

ध्यान केंद्रित करने वाले खेल खेलना

ये सभी दिमाग की कोशिकाओं को सक्रिय रखते हैं।

7. तनाव पर नियंत्रण

आधुनिक जीवन में तनाव सबसे बड़ा कारक है जो याददाश्त को प्रभावित करता है। आयुर्वेद मानता है कि सत्त्वगुण की वृद्धि और राजस-तामस की कमी से मानसिक शांति मिलती है। योग, ध्यान, संगीत और सकारात्मक सोच तनाव को कम कर स्मरण शक्ति को बनाए रखते हैं।

8. कुछ घरेलू आयुर्वेदिक गुस्खे

► सुबह खाली पेट 4-5 भीगे बादाम, काली मिर्च और मिश्री के साथ पीसकर दूध में मिलाकर पीएं।

► ब्रात्सी घृत (1 चम्मच) गुनगुने दूध के साथ लेना लाभकारी है।

► शहद में पिसा हुआ दालचीनी पाउडर मिलाकर चाटना भी याददाश्त बढ़ाने में सहायक है।

► अश्वगंथा चूर्ण आधा चम्मच गुनगुने दूध के साथ रात को लेना लाभदायक है।

याददाश्त को मजबूत बनाने का कोई तात्कालिक या जारी होने वाला उपाय नहीं है।

यह निरंतर अभ्यास, सही जीवनशैली और संतुलित आहार से संभव है। आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि मस्तिष्क की शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रकृति प्रदत्त साधनों का उपयोग करना सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है।

यदि हम आयुर्वेदिक आहार, जड़ी-बूटियों, योग-प्राणायाम और दिनचर्याओं को जीवन का हिस्सा बना लें, तो न केवल हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, बल्कि जीवन भी तनावमुक्त, संतुलित और स्वस्थ बनेगा।

संत रामप्रसाद जी: माँ काली के परम भक्त बंगाल की पवित्र भूमि और संत रामप्रसाद का अवतरण

भा

इयो और बहनों, बंगाल की धरती कितनी बोल और भावुक है, कितनी मधुर और बड़े-बड़े संत, महात्मा, भक्त और महापुरुषों ने जन्म लिया। इसकी गोद में, सोने जैसी चमकती धूल में, श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मधुर और दिव्य लीला दिखाई, जो भगवान की इतिहास में एक अनोखी बात है। चैतन्य महाप्रभु की लीला समाप्त होने के लागत तीन सौ साल बाद, इसी बंगाल ने शाक्त संत रामप्रसाद सेन को जन्म दिया। आज भी बंगाल के गाँव-गाँव में रामप्रसाद जी की शक्ति भक्ति से भरे गीत लोगों के गले का हार बने हुए हैं। खेत में काम करने वाले किसान, सड़क पर काम करने वाले मजदूर, गाय-भैंस चराने वाले लोग और दूसरे कामों में लगे हुए जन, जब रामप्रसाद जी के गीत गते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय की बेटी माँ काली खुद साहित्य के रूप में अवतरित हो गई है। जन-जन के जीवन में काली का भक्ति रूप उत्तर आया है। न सिर्फ बंगाली शाक्त साहित्य में, बल्कि पूरे भारतीय संत साहित्य में संत रामप्रसाद का नाम अमर और कभी न मिटने वाला है। वे लोकायक संत थे। पढ़े-लिखे और अनपढ़ सब उनके गीतों को आसानी से समझ लेते हैं – यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा राज है। उन्होंने जीवन भर शक्ति की उपासना की। हे माँ काली, भक्त रामप्रसाद जी ने तेरी भक्ति में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, हमें भी वैसी ही भक्ति देना।

यह समय बड़ा उथल-पुथल भरा था। संत रामप्रसाद बंगाल के प्रसिद्ध शासक नवाब सिराजुद्दौला के समकालीन थे। उन दिनों इस्ट इंडिया कंपनी सिराज को गद्दी से हटाकर अंग्रेजों की सत्ता कायम करने की कोशिश कर रही थी। भारत में धीरे-धीरे अंग्रेजों की ताकत बढ़ रही थी और मुगल राज का तेजी से पतन हो रहा था। राजनीतिक उठापटक के इस दौर में रामप्रसाद जी ने जन्म लेकर बंगाली समाज को शक्ति भक्ति से समृद्ध किया। उन्होंने शाक्त योग की साधना की। दुर्गा भक्ति के समुद्र में पूरी तरह डुबकी लगाकर अपना जीवन सफल और धन्य कर लिया। वे देवी के परम भक्त थे। माँ, तेरे चरणों में समर्पित होने वाला ऐसा भक्त दुनिया में कम ही मिलता है। बंगाल में धर-धर शक्ति पूजा की परंपरा है। रामप्रसाद जी का परिवार भी शक्ति था। उनके पूर्वज साधारण गृहस्थ थे। हे जगदंबे, तेरी कृपा से ऐसे भक्त पैदा होते हैं जो दुनिया को तेरी भक्ति का रस पिलाते हैं।

जन्म और बाल्यकाल की गरीबी में भक्ति का उद्य

संत रामप्रसाद जी ने बंगाल प्रांत के हालीशहर के पास कुमारहट्ट गाँव में संवत् 1775 विक्रमी में जन्म लिया। उनके पिता रामराम सेन थे। उनकी उम्र बहुत कम थी। रामप्रसाद जी का बचपन बड़ी गरीबी में बीता। लेकिन बाल्यावस्था से ही उन्होंने दुर्गा में भक्ति और पढ़ाई में रुचि दिखाई। उन्हें बंगाल, संस्कृत, फारसी और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। हे माँ काली, बचपन से ही तेरे भक्त ने तेरी और रुद्धान दिखाया, यह तेरी ही कृपा है। जवानी में रामप्रसाद जी कलकत्ता आ गए। वहाँ उनके परिचित बुकुलचंद्र घोषाल, जो किसी राज्य के दीवान थे, ने उन्हें बहिखाता लिखने के लिए नौकरी दे दी। रामप्रसाद जी ने वहाँ देवी से जुड़े कई पद रचकर लिख दिए। एक जगह उन्होंने जगजननी से प्रार्थना की कि हे माता, मुझे बहिखाता लिखने में जरा भी अनंद नहीं आता। कृपा करके मुझे अपने

चरणों की भक्ति दे दो। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरी कभी न खत्म होने वाली निधि हो।

उनका मन नौकरी से ऊब गया। दीवान ने बहुत कोशिश की कि वे काम में लगे रहें, लेकिन रामप्रसाद जी का मन तो देवी के चरण कमलों के सुगंध का रस चख चुका था। दीवान ने उनकी जीविका के लिए बीस रुपये की पेशन की व्यवस्था कर दी। फिर कृष्णनगर (नदिया) के राजा कृष्णचंद्र की राजसभा में उनका परिचय कराया। कृष्णचंद्र, शाकों और बंगाली जनता ने उन्हें कविरंजन की उपाधि दी। राजा कृष्णचंद्र ने जीविका के लिए सौ बीघा जमीन दी। रामप्रसाद जी ने दुनिया की माया के बंधनों को तोड़कर शक्ति भक्ति के राज्य में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि काली का नाम उच्चारण करना चाहिए। लोग कहेंगे पागल हो गया है, गाली देंगे, लेकिन इसकी जरा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार में अच्छे-बुरे दोनों हैं। अच्छा काम करना ही बेहतर है। काली के नाम रूपी तलवार से माया और संसारिक बंधनों को काट डालना चाहिए। जगत के झूठ और माया ही विनाश के कारण हैं। रामप्रसाद जी को संसार से वैराग्य हो गया। वे देवी की उपासना में लग गए। रात-दिन काली के पदों का चिंतन ही उनका मुख्य काम हो गया, उनका धर्म हो गया। उन्होंने साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर जगद्वात्री अस्मिका के चरणों में खुद को समर्पित किया कि क्या मातृत्व सिर्फ कहने भर का है? सिर्फ जन्म देना मातृत्व नहीं है। माँ तो अपने बच्चे की पीड़ा जानती है। जन्म देने वाली माँ दस महीने और दस दिन गर्भ की पीड़ा सहती है। लेकिन मेरी माँ तो पूछती भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। बच्चे से गलती या अपराध हो जाने पर संसारी माता-पिता उसे सही रास्ता बताते हैं। लेकिन माँ, तुम देख रही हो कि मौत मुझे मारने के लिए कितनी तेजी से आ रही है, लेकिन तुम निश्चिंत हो। तुमने ऐसा व्यवहार कहाँ से सीखा? अगर तुम भी अपने पिता हिमाचल की तरह कठोरता अपनाती हो, तो जगजननी का नाम छोड़ दो। हे माँ, तेरे भक्त की ऐसी करुण पुकार सुनकर भी तू चुप कैसे रह सकती है? हमें भी वैसी भक्ति दे कि हम तेरे चरणों में लीन हो जाएँ।

गुरुकी शरण और नवाब से भैंट का दिव्य प्रसंग

संत रामप्रसाद जी के गुरु श्रीनाथ दत्त थे। गुरु के चरण कमलों में उनका गहरा लगाव था। उन्होंने मन को समझाया कि तुम संसारी वैभव छोड़कर मृत्युंजय की शरण में जाओ, यही भव रोग की दवा है। एक बार गंगा की बीच धारा में बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला से उनकी मुलाकात हुई। गर्मी का मौसम था। राजनौका तेजी से भागीरथी के पानी में कल-कल, छप-छप की आवाज करती जा रही थी। राजनौका के ठीक सामने थोड़ी दूर एक साधारण नाव में संत रामप्रसाद सितार बजाकर मधुर राग-रागिनी में काली का मनोरंजन कर रहे थे। नवाब ने रामप्रसाद जी के दर्शन को अपना बड़ा सौभाग्य माना और राजनौका पर उन्हें बुलाया। बंगाल का सारा राज वैभव उनके चरणों पर द्वाक गया। नवाब ने पद सुनाने की विनती की। उन्होंने शास्त्रीय संगीत गाना शुरू किया। नवाब सिराज ने विनम्र होकर कहा कि महाराज, मुझे शास्त्रीय संगीत में जरा भी श्वर नहीं मिल रहा। मुझे तो आपके दिल से निकले काली महाशक्ति के स्तुति भरे पद सुनने की इच्छा है। संत रामप्रसाद जी ने पद गाना शुरू किया। नवाब सिराज ने विनम्र होकर कहा कि तुमने मुझे बंधनों में बाँध दिया। 'माँ' शब्द तो ममता का प्रतीक है, बच्चा रोए तो माँ गोद में ले लेती है। संसार की यही रीति है, सब माताएँ ऐसा करती हैं। तो क्या मैं संसार से अलग हूँ? तुम मुझे प्यार नहीं करतीं। माँ, एक बार मेरी आँखों की पट्टी हटा दो, मुझे अपने श्रीचरणों का दर्शन करने दो। एक जगह रामप्रसाद जी की बड़ी अनोखी बात है, माँ काली के प्रति व्यंग्य कि माँ, जिन चरणों की इच्छा स्वयं भगवान शिव करते हैं, उन्हें



भय से तुमने महिषासुर को दे दिया। सच है, जिसके हाथ में तलवार है, तुम उसी की बात सुनती हो। प्राण बचाने के लिए तुम महिषासुर की अमर और शाश्वत शरण हो गई। हे माँ, तेरे भक्त की ऐसी पुकार हमें भी तेरी भक्ति में डुबो देती है।

अंतिम क्षण और महाप्रयाण की दिव्य लीला

संवत् 1832 विक्रमी में उन्होंने नश्वर शरीर त्याग दिया। मृत्यु से पहले उन्होंने काली की विधि से पूजा की और फिर पद गाते हुए माँ के धाम में प्रवेश किया। ऐसी मान्यता है कि काली प्रतिमा का विसर्जन होते समय वे गंगा में विरह से व्याकुल होकर कूट पड़े और दूसरे लोक चले गए। अंतिम समय में उन्होंने कहा कि सावधान, नौका डूब रही है। हे असावधान मन, समय बीतता जा रहा है लेकिन तुमने काली की भक्ति नहीं की। तुमने नौका पर बेकार चीजें रखकर उसे भारी बना दिया। दिन भर तुमने घाट पर इंतजार किया, शाम को धारा के पार हो जाओगे। तुमने अपनी पुरानी नौका पापों से लाद दी है। अगर तुम संसार सागर पर करना चाहते हो तो केट मल्लाह रूपी परमात्मा का स्मरण करो। धीरण और ऊँची लहरों से डरकर छह मल्लाह – पाँच कर्मेंद्रिय और चित्त – ने साथ छोड़ दिया है। परमात्मा ही पार लगाएँगे, विश्वास रखो। भगवती दुर्गा-परमात्मा शक्ति में उनका अटल विश्वास था, दृढ़ निष्ठा और भक्ति थी। उनकी भक्ति मौलिकी थी। उन्होंने मृत्यु से कहा कि तुम क्षण भर रुक जाओ। मुझे जोर-जोर से माँ का नाम लेने दो। यद्यपि तुम मुझे ले ही जाओगे, लेकिन मुझे इसकी जरा चिंता नहीं। क्या मैंने देवी के नाम की माला व्यर्थ पहनी है? महेश्वरी ही मेरी मालिक-जीमादार हैं और मैं उनका सेवक-किसान हूँ। यद्यपि मैं स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, फिर भी मैंने उनका सारा कर दे दिया है, कुछ बाकी नहीं। क्या माँ के जीवन नाटक को दूसरे समझ सकते हैं? जब ब्रिलोचन – साक्षात शिव – उनकी महिमा नहीं समझ पाते, तो क्या मैं उनका रहस्य जान सकता हूँ। दुर्गा का नाम ही मेरे लिए अमृतमय मुक्ति क्षेत्र है। अंतिम साँस छोड़ते हुए उन्होंने करुणा भरी आवाज में कहा कि माँ, मेरे जीवन का खेल समाप्त हो गया। अथि आनंदमयी माँ, समाप्त हो गया। मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया था। मैंने पृथ्वी की धूल में अपना जीवन खेल खेला। अथि, हिमाचलनंदिनी। इस समय काल मेरे सिर पर नाच रहा है, मुझे मृत्यु का भय सता रहा है। बचपन के दिन मैंने खेल-कूट में गँवा दिए, मुझे सारा समय प्रार्थना में लगाना चाहिए था। माँ, अब मैं शक्तिहीन और बूढ़ा हूँ, मुझे बताओ क्या करूँ। माँ, तुम शक्तिस्वरूप हो, मेरे जगत के अविद्या-माया-अंधकार से येरे होने पर माँ काली का आह्वान किया कि माँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, चारों तरफ अंधेरा है, काली रात है। तुम कठोर हो। मैं कहीं का नहीं रहा, जैसे चकोर को अमृत न मिला हो। मेरे भाग्य का भाग्य इतना क्लूर है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कर बैठता हूँ कुछ और। मेरा मन ऐसी संर्घष भरी रिश्ति में पागल सा हो गया है। उनकी भक्ति से महाकाली के चरण स्पंदित हो उठे कि माँ, मैंने क्या दोष किया कि तु

पेट्रोल के दामों में बढ़ोतारी पांच सालों का सफर



पेट्रोल हमारे रोजमर्या की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार हो, बाइक हो या बस, सबको चालने के लिए पेट्रोल चाहिए। लेकिन पिछले पांच सालों में पेट्रोल के दामों में काफी बदलाव आया है। कुछ राज्यों में दाम बहुत बढ़े हैं, तो कुछ में बिलकुल नहीं। मध्य प्रदेश और हरियाणा में 15 रुपये की बढ़ोतारी हुई है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 14 रुपये बढ़े। सबसे ज्यादा अंडमान में 35 रुपये की बढ़ोतारी हुई। जबकि झारखंड में कोई बदलाव नहीं आया। क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि ऐसे बदलाव सहन कर सके?

राज्यों में पेट्रोल के दामों की बढ़ोतारी: कहाँ कितना असर?

पिछले पांच सालों में पेट्रोल के दामों में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग बदलाव देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा में पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। यानी अगर 2020 में 80 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदते थे, तो अब 95 रुपये देने पड़ते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह बढ़ोतारी 14 रुपये की है। यहां के लोग कहते हैं कि रोज की यात्रा अब महंगी हो गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अंडमान और निकोबार द्वीपों की है। वहां पेट्रोल के दाम 35 रुपये बढ़े हैं, जो 49 प्रतिशत की बढ़ोतारी है। 2021 में पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल 47 रुपये लीटर था, अब 82 रुपये हो गया है। यह बहुत ज्यादा है, क्योंकि द्वीपों में सामान पहुंचाना पहले से ही मुश्किल है।

झारखंड में स्थित अलग है। वहां पांच सालों में पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतारी नहीं हुई। यांची में 2021 में पेट्रोल 82.80 रुपये लीटर था, अब 82.46 रुपये है। यानी थोड़ा कम भी हुआ है। यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे कुछ राज्य दामों को नियंत्रित रख सकते हैं। पंजाब में 23 रुपये (27 प्रतिशत) की बढ़ोतारी हुई है। पश्चिम बंगाल में 20 रुपये (24 प्रतिशत), तेलंगाना में 20 रुपये, महाराष्ट्र में 20 रुपये और मिजोरम में 18 रुपये की बढ़ोतारी देखी गई है। ये अंकड़े लोकसभा में 21 अगस्त को दिए गए जवाब से लिए गए हैं। कुछ राज्यों में बढ़ोतारी कम है,



जैसे गुजरात में 10 रुपये। लेकिन कुल मिलाकर, देश के ज्यादातर हिस्सों में दाम बढ़े हैं। क्या यह बढ़ोतारी हर जगह एक जैसी क्यों नहीं है?

क्योंकि हर राज्य वैट अलग लगाता है। मध्य प्रदेश वैट लगाने वाले देश के पांचवें नंबर के राज्य में है। इससे दाम और बढ़ जाते हैं। सोचिए, अगर सभी राज्य वैट कम कर दें, तो कितनी राहत मिल सकती है।

यह बदलाव 2021 से 2023 तक लगातार बढ़ते रहे। 2024 में लोकसभा चुनावों की वजह से दाम स्थिर रहे। पिछले सात महीनों से कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए हैं, तो क्या दाम फिर बढ़ेंगे? यह सवाल हर आम आदमी के मन में है।

दाम बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं?

पेट्रोल के दाम बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें हैं। भारत 80 प्रतिशत से ज्यादा तेल आयात करता है। अगर वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है, तो यहां भी दाम बढ़ जाते हैं। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल के दाम आसमान छू गए थे। उस वक्त देश में पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया। लेकिन 2024 में दाम स्थिर हैं, क्योंकि वैश्विक बाजार में तेल सस्ता हुआ है।

दूसरा बड़ा कारण टैक्स है। केंद्र सरकार एक्साइज इयूटी लगाती है, और राज्य वैट। मध्य प्रदेश में वैट ज्यादा है, इसलिए दाम ज्यादा बढ़े। लोकसभा में बताया गया कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम राष्ट्रीय

औसत से ज्यादा बढ़े हैं। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी वैट की वजह से दाम प्रभावित हुए। अंडमान में दाम इतने बढ़े क्योंकि वहां परिवहन लागत ज्यादा है। सामान जहाज से जाता है, तो महंगा पड़ता है। झारखंड में दाम नहीं बढ़े, शायद वहां सरकार ने वैट कम रखा या सब्सिडी दी।

तीसरा कारण मुद्रा स्फीति है। रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले कम हुई, तो आयात महंगा हो गया। साथ ही, कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आया। 2020 में दाम कम थे, क्योंकि लॉकडाउन में मांग घटी। लेकिन 2021 से मांग बढ़ी, तो दाम भी बढ़े। सरकार कहती है कि वह दाम नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकार ने इंफ्लेशन नहीं रोका। सोचने वाली बात है कि क्या हम तेल पर इतने निर्भर रहें? इलेक्ट्रिक वाहन या सौर ऊर्जा जैसे विकल्प अपनाने से क्या फायदा हो सकता है? यह सवाल हमें आगे की योजना बनाने पर मजबूर करता है।

आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है?

पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता है। एक परिवार जो रोज 50 किलोमीटर बाइक से सफर करता है, उसका महीने का खर्च 500-1000 रुपये बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश में 15 रुपये की बढ़ोतारी से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। सब्जी, दूध, अनाज सबके दाम बढ़े, क्योंकि ट्रक वाले ज्यादा पेट्रोल खर्च करते हैं। राजस्थान में किसान कहते हैं कि ट्रैक्टर चलाना महंगा

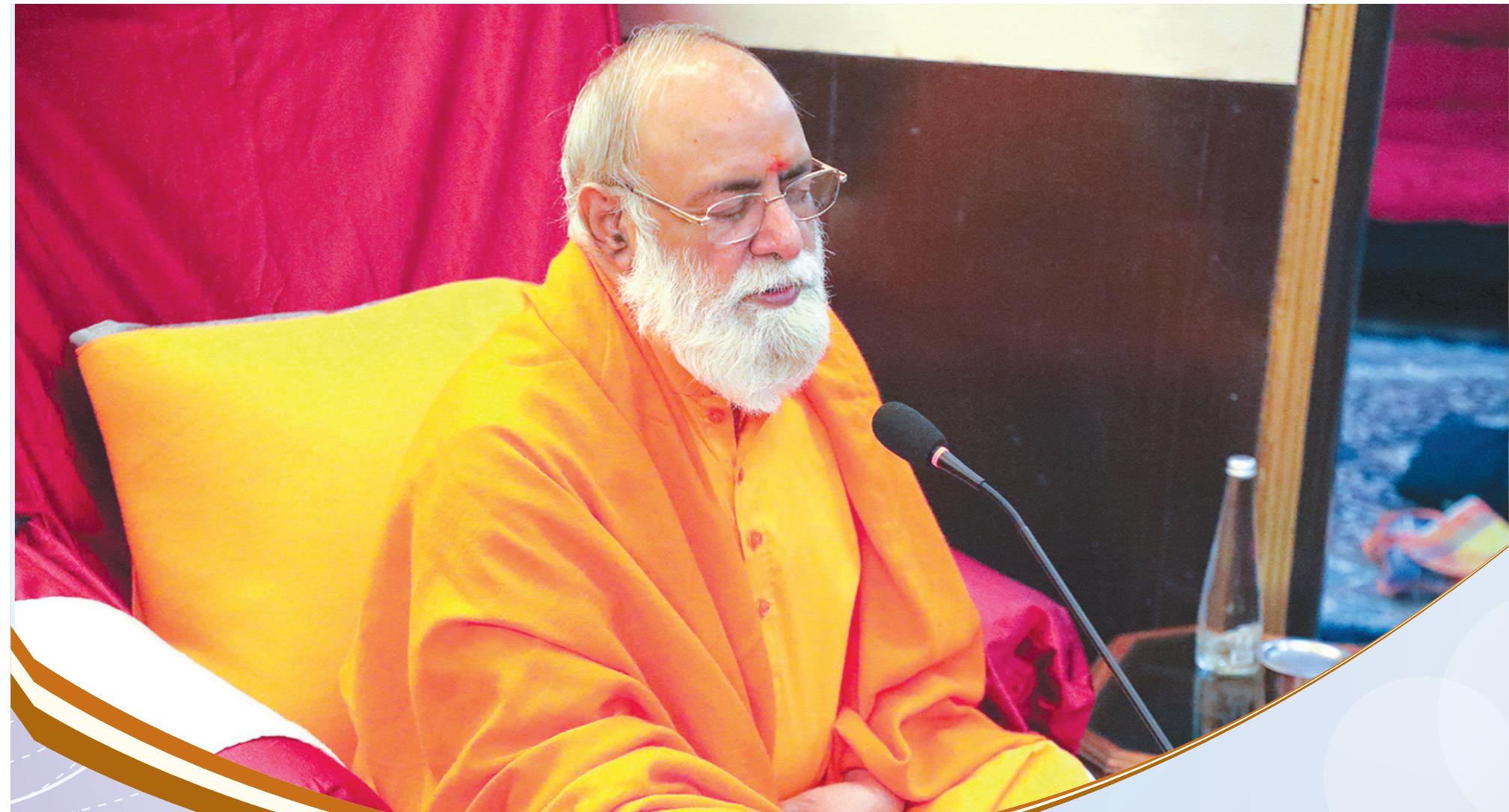
हो गया। उत्तर प्रदेश में ऑटो वाले किराया बढ़ा रहे हैं। अंडमान जैसे द्वीपों में तो स्थिति और खराब है। वहां 35 रुपये की बढ़ोतारी से पर्यटन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि टिकट महंगे हो जाते हैं।

झारखंड में दाम नहीं बढ़े, तो वहां के लोग खुश हैं। लेकिन पूरे देश में इंफ्लेशन बढ़ा है। लोग कहते हैं कि सैलरी बढ़ती नहीं, लेकिन खर्च बढ़ते जाते हैं। छोटे व्यापारी, ड्राइवर, किसान सब प्रभावित हैं। महिलाएं कहती हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया। क्या सरकार राहत दे सकती है? जैसे वैट कम करके या सब्सिडी देकर। लेकिन सरकार कहती है कि टैक्स से सङ्केत, अस्पताल बनते हैं। यह दोनों तरफ की बात है। सोचिए, अगर दाम कम हों, तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? लेकिन अगर ज्यादा बढ़ें, तो आम आदमी कैसे जिएगा? यह संतुलन बनाना जरूरी है।

भविष्य में ज्यादा उम्मीद है?

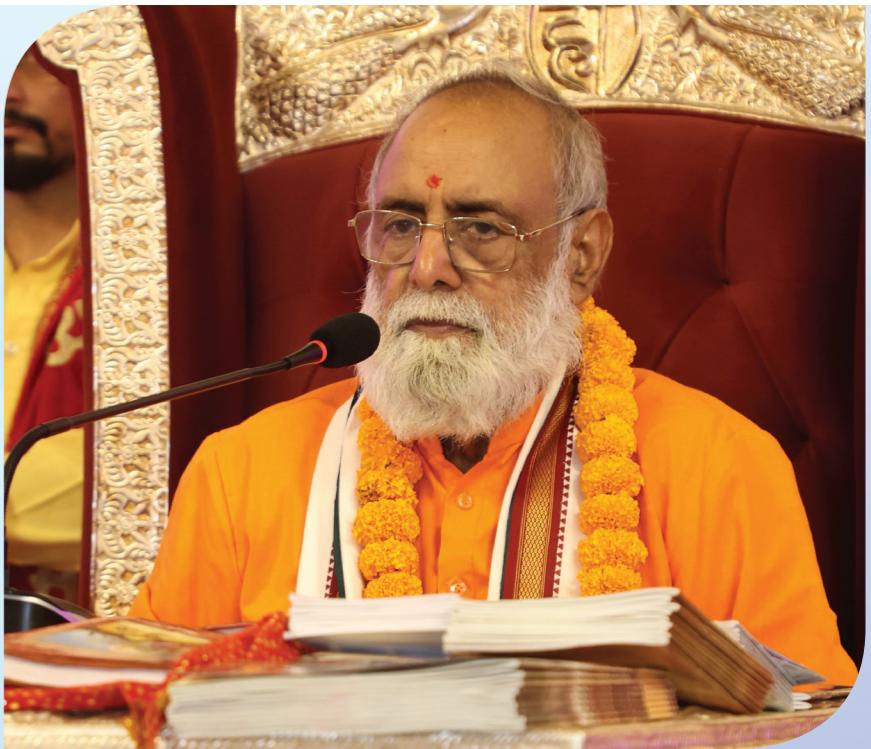
पेट्रोल के दामों का भविष्य वैश्विक घटनाओं पर निर्भर है। अगर तेल उत्पादक देश उत्पादन कम करें, तो दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं। सरकार इंवी को बढ़ावा दे रही है। 2030 तक 30 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक होने का लक्ष्य है। इससे पेट्रोल की मांग कम हो सकती है, और दाम स्थिर रह सकते हैं। कुछ राज्य वैट कम करने की सोच रहे हैं। जैसे 2024 में चुनावों के कारण दाम स्थिर रहे।

लेकिन चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन से तेल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। भारत को तेल आयात करना चाहिए। सौर, पवन ऊर्जा से बिजली बनाकर इंवी चार्ज करें। झारखंड जैसा उदाहरण अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य वैट की समीक्षा कर सकते हैं। अंडमान में विशेष राहत की जरूरत है। कुल मिलाकर, हमें सोचना चाहिए कि तेल पर निर्भरता कम कैसे करें। क्या हम वैकल्पिक ईंधन की तरफ बढ़े? यह विचार हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है।



गुरुदेव जी ज्ञान के भंडार हैं

दिल्ली पुलिस के पू. स्पेशल कमिशनर श्री पी एन अब्दुल जी ने कहा कि मैं 15 साल से परम पूज्य गुरुदेव जी के संयर्क में हूं। इससे पहले मैं सनातन संस्कृति और परंपराओं में विश्वास नहीं रखता था। पूज्य गुरुदेव जी पाठ देकर कहते हैं कि आप विश्वास करें, पाठ करें। गुरुदेव जी बताते थे कि लर रोग का इलाज लगारी संस्कृति में होता है। एसा कोई भी रोग नहीं है जिसका इलाज न हो। एक दिन इन्होंने पूज्य गुरुदेव जी से डैंडक जिसका एलोपेथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर ट्रीटमेंट करने के लिए प्रार्थना की। पूज्य गुरुदेव जी ने लगारी परिव्रक्ति नदियों के जल में कुछ जड़ी-बूटियां और गंगाजल निलाकर 'काटन कार्यपारेशन आक इंडिया' के वेयरनेन के सिर को धो दिया जिनके सिर में बहुत डैंडक थी। कभी-कभी तो युजाने से खून निकल आता था। इसके बाद पूज्य गुरुदेव जी ने नार्मल शैम्पू से उनका सिर धो दिया। सिर जब सूख गया तब माइक्रोस्कोप से चैंक किया गया तो डैंडक बिल्कुल खल लो गई थी। इसके प्राकिया की रिकार्डिंग भी की गई थी। उनकी डैंडक बिल्कुल खल लो गई। इसके बाद समाजमें यह ट्रीटमेंट किया गया और टेलीकास्ट भी किया गया। अंग्रेज कहते हैं कि केवल एक निनट में शी ये कैसे मुक्तिकरण करता है। उनका कहना है कि रामायण भी एक कहानी है। गुरुदेव जी द्वारा बताया गया युटीआर्ड का इलाज भी मंत्रों पर आधारित है। इस औषधि में केवल शुद्ध जल है। मैंने कुछ व्याकियों और महिलाओं को दिया और उनको भी दिया जो हिन्दुत्व को गाती बकरते हैं लेकिन ठीक होने के बाद उन्होंने कहा कि यह तो कमाल है। गुरुदेव ज्ञान के भंडार हैं। लगारी कोशीश यह रहनी चाहिए कि नई-नई औषधियां खों दें। गुरुदेव एक्सप्रेसिट करते रहते हैं और जब वह सफल हो जाता है तो दूसरों को देते हैं। गुरुदेव जी से प्रार्थना है कि लगारी वीमारियों और समस्याओं का निदान करें और गंग प्रदान करें ताकि इन प्रसन्न और खुशी रहें।



करोड़ों में से किसी एक को होता है यह रोग मां दुर्गा के पाठ से हुआ समाप्त

भयंकर दुष्प्रभाव हैं अंग्रेजी दवाइयों के

परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने समाजमें कहा कि यदि किसी को हृदय रोग हो जाए तो उसके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उनके अनेकों दुष्प्रभाव भी हैं। हृदय रोग में सबसे महत्वपूर्ण दवा खून को पतला करने के लिए होती है। खून के बढ़ाव को बढ़ाने के लिए भी दवाइयां होती हैं इसके साथ-साथ अन्य कारणों के लिए भी दवाइयां दी जाती हैं जिनके साइड इफेक्ट इस प्रकार हैं कि कब्ज़ हो जाती है, शरीर में लाल चक्करे हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, किंडनी की समस्या हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, सांस फूलने लगता है और चला नहीं जाता। हालत यह हो जाती है कि मरीज एक रोग को ठीक करने के लिए दवा लेता है तो दूसरे रोग भी हो जाते हैं और उनके लिए भी जो दवाइयां ली जाती हैं उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसी अवश्या एक हार्ट की समस्या के लिए ऐसी औषधिका आविष्कार हो जाए जिससे इस स्थिति से छुटकारा मिल जाए, ऐसी मां दुर्गा की कृपा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।

जयपुर के श्री पवन कुमार शर्मा ने बताया कि मेरी छोटी पोती धूकी शर्मा जो तीन वर्ष की है को जब बुखार होता था तब 103 डिग्री से ऊपर चला जाता था। उसके हाथ-पैर निकिंग हो जाते थे और आँखें ठहर जाती थीं। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह मर गई है। ऐसा कुछ मिनटों के लिए होता था। हम सब घबरा जाते थे। डाक्टर साहब ने बताया कि यह रोग करोड़ों में से किसी एक को होता है। यह खतरनाक दौरा होता है। हमने उसे जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल जे.के.लॉन में भी दिखाया था लेकिन कोई हल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन मैं पूरे परिवार के साथ बृंदावन समाजमें गया लेकिन यहां भी अचानक उसे फिर से दौरा पड़ा। हम बहुत घबरा गए। जहां हम रुके हुए थे वहीं से रात्रि को ही सीधा अस्पताल लेकर जाना पड़ा। धूकी को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। हम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि हमें समाजमें बुलाओ। ऐसा सौभाग्य हुआ कि हम समाजमें गर् और गुरुदेव जी महाराज के स्टेज पर भी जाने का अवसर मिला। हमने विशेष कृपा ग्रहण की जिसके प्रभाव से और गुरुदेव जी के आशीर्वाद से वह ठीक है। अब उसे कोई दौरा नहीं पड़ता है।

निष्क्रिय पैर में आई जान

कोटा, राजस्थान के श्री धनश्याम शर्मा ने बताया कि मेरे पिता जी श्री कृष्ण लाल शर्मा जी, जिनकी उम्र 85 वर्ष है, पैर की तकलीफ से परेशन हो गये थे। 25 जनवरी 2023 को उनके बांग पैर ने अचानक काम करना बंद कर दिया। मैंने उन्हें कोटा के डा. अमित देव जी को दिखाया। उन्होंने एमआरआई करवाई और कहा कि रिपोर्ट में कमर की नस दीवी हुई आ रही है। उन्होंने सात दिन की दवा दी लेकिन फिर भी आराम नहीं आया। इसके बाद मैंने डा. सरदाना को दिखाया फिर भी आराम नहीं आया। मैं अपने पिता जी के लिए दिव्य बीज मंत्रों का पाठ बराबर करता रहा। इसके बाद मैंने परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से सवनवारक औषधि ग्रहण की। इसका उत्योग मैंने उहे स्नान और चिलाने के लिए किया। पिता जी को इससे आराम आ गया। 28 फरवरी 2023 को मैंने उहे डा. गौतम को दिखाया। डाक्टर साहब ने एक्सरे करवाया और बताया कि सब कुछ ठीक है।

असाध्य ब्रेस्ट कैंसर का हुआ सफल आपरेशन

उदयपुर, राजस्थान की श्रीमती सावित्री माली ने बताया कि मैंने 2017 में बृंदावन समाजमें पूज्य गुरुदेव जी से बीज मंत्रों की कृपा ग्रहण की थी। इसके बाद 2022 में मुझे ज्ञात हुआ कि मैं ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हूं। मैंने अल्ट्रासाउंड बोयासी करवाई। इसके बाद पैट सिटी करवाई तब मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। डाक्टरों ने बताया था कि यह बहुत ही जटिल है और इसका आपरेशन असामी ने नहीं हो सकता, इसमें खतरा भी है। मैं बीज मंत्रों का पाठ करती रही और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा मां से प्रार्थना करती रही कि यह कार्य सफल हो। आपरेशन के समय मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ और न कोई समस्या हुई। इसके बाद मैंने डाक्टर आशीर्वादियों से 2023 में जांच करवाई वहीं से और प्रार्थना है कि लगारी वीमारियों और समस्याओं का निदान करें और गंग प्रदान करें ताकि इन प्रसन्न और खुशी रहें।

विदेश से ली एमबीबीएस की डिग्री अब कर रही है इंटर्नशिप

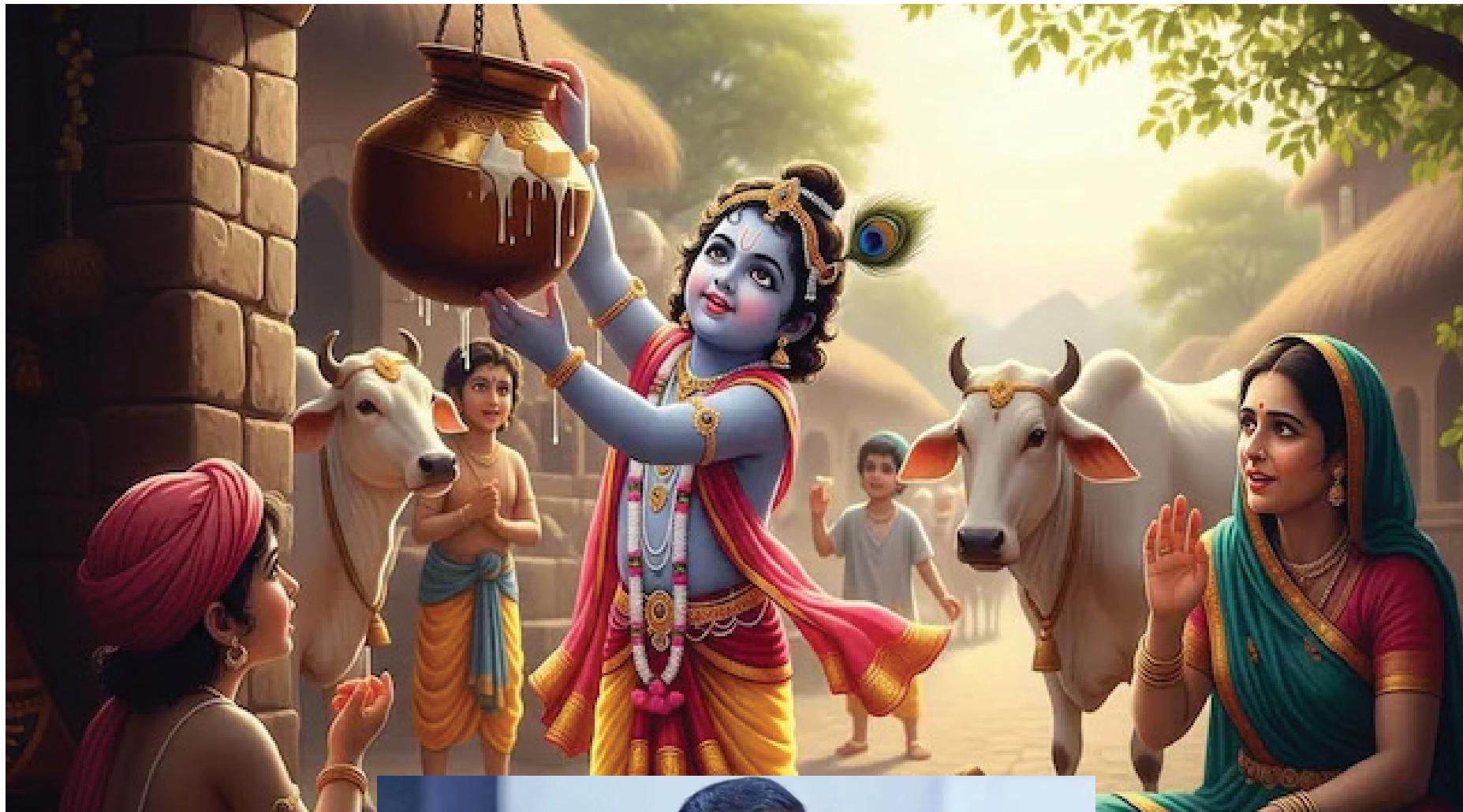
उना, हिमाचल प्रदेश के श्री बुजमोहन लाल ने बताया कि मेरी बेटी डाक्टर बनना चाहती थी। इसके लिए उसने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से बीज मंत्रों की कृपा ली थी। मैंने भी पाठ ग्रहण किया था। इसके प्रभाव से मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में दाखिला मिल गया। 21 अगस्त 2021 में मेरी बेटी को एमबीबीएस की डिग्री मिल गई। इसके बाद मेरी बेटी ने भारत में इलिजिबिलिटी टैस्ट (एफएमजीई) 2022 में पास कर लिया और अब वह दीन दयाल यादायां अस्पताल (रिपन) में अपनी इंटर्नशिप कर रही है। यह सब दिव्य बीज मंत्रों के पाठ के प्रभाव से हुआ है।

चेहरे का लकवा हुआ समाप्त

पटियाला, पंजाब की श्रीमती नाम कैलासी ने बताया कि मेरे बेटे गगनदीप सिंह को ब्रेन हैमरेज हो गया था। मैंने उसे 22 नवंबर को ब्रेन एंड मल्टीसेंशनल हास्पिटिल 22 नवंबर फार्ट, भूमिन्द्रा रोड पर डा. सरदेवा को दिखाया था। वहां से उसके इलाज करवाया गया। समय कम था क्योंकि उसे इंग्लैंड जाना था। मैंने अपने बेटे के लिए पाठ किया। दवा और दुआ दोनों के प्रभाव से वह समय से पहले ही ठीक हो गया और फ्लाइट पकड़कर इंग्लैंड चला गया। उसे इंग्लैंड गये हुए एक साल हो गया है। वह भी पाठ करता है और उसे कोई समस्या नहीं है। गुरु जी की कृपा से और पाठ के प्रभाव हमारा पूरा परिवार सुखी है।

क्या स्थान में श्रीकृष्ण 'माखनचोर' थे?

मध्य प्रदेश में नई बहस



@ आनंद मीणा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वे भगवान श्रीकृष्ण को "माखनचोर" कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि यह शब्द उन्हें बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। उनका मानना है कि भगवान श्रीकृष्ण का मक्खन तोड़ना या मटकी फोड़ना वास्तव में एक विद्रोह का प्रतीक था, जिसे गलत ढंग से "माखनचोरी" कहा जाने लगा।

कृष्ण की लीलाओं की परंपरागत छवि

दरअसल, श्रीकृष्ण को बचपन से ही "माखनचोर" नाम से पूजा जाता रहा है। साहित्य, संगीत, भजन और चित्रकला में यह स्वरूप नटखटपन और बाल-लीलाओं का प्रतीक रहा है। दही-हांडी की परंपरा भी इसी माखनचोर स्वरूप से जुड़ी है।

विद्रोह का प्रतीकथी मटकी फोड़लीला

अपने बयान में मोहन यादव ने कहा कि भगवान



श्रीकृष्ण का मक्खन मटकी फोड़ना, कंस की नीतियों के खिलाफ एक विद्रोह था। मक्खन दुश्मन तक न पहुँचे, इसलिए श्रीकृष्ण ने माखन की मटकी फोड़ने का रास्ता चुना। उन्होंने इसे बालसुलभ शरारत न मानकर, एक सामाजिक और राजनीतिक संदेश बताया मुख्यमंत्री के बयान के बाद राज्य का कल्वर डिपार्टमेंट सक्रिय हो

गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। धार्मिक गुरुओं और विद्वानों से अपील की जाएगी कि कृष्ण की माखन चोरी की कहानियों को "विद्रोह" के रूप में समझाया जाए।

विपक्ष का पलटवार

विपक्ष ने मोहन यादव पर इतिहास और सनातन धर्म की परंपराओं को बदलने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी सुविधा से नया इतिहास लिखना चाहते हैं, जबकि सदियों से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उसी रूप में होता आया है। उन्होंने यहां तक कहा कि सीएम को पहले अपने "जनादेश और बोट की सच्चाई" पर जवाब देना चाहिए।

राजनीतिक और धार्मिक पहलू

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद महज शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपा है।

दरअसल, मोहन यादव की सरकार राज्य में 'कृष्ण पथ' धार्मिक सर्किट बना रही है, जिसके तहत 322 मंदिरों का सर्वे किया जा चुका है। उज्जैन, जो कि यादव का राजनीतिक गढ़ है, को इसका प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, आम लोगों से लेकर विपक्ष तक सभी ने इसे हाथों-हाथ लिया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर मीम्स और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।

कर्नाटक के पूर्व DGP ओमप्रकाश की हत्या

पत्नी ने ही दिया वारदात को अंजाम, पारिवारिक कलह बनी वजह

अंकुर विश्वकर्मा

कर्नाटक पुलिस विभाग के पूर्व महानिदेशक ओम प्रकाश की रविवार शाम हत्या हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह वारदात उनकी पत्नी ने ही की। घटना बैंगलुरु के पॉश इलाके एचएसआर लेआउट में उनके घर पर हुई। हत्या के बाद पत्नी ने खुद ही पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने पत्नी और बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

घटनास्थल और पहली सूचना

रविवार शाम एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में फोन घनघनाया। कॉलर ने घबराई हुई आवाज में बताया "मैंने अपने पति की हत्या कर दी है।" पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वहाँ का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। कर्मसुके के भीतर खून से लथपथ 68 वर्षीय ओम प्रकाश पड़े थे। पास ही उनकी पत्नी मौजूद थी, जिसने वारदात स्वीकार कर लिया।

पोस्टमॉर्टम और क्रेस दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमॉर्टम के लिए होसुर रोड स्थित सेंट जॉन्स अस्पताल भेजा। वहाँ, एचएसआर लेआउट थाने में पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में साफ हुआ है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था।

आईपीएस अधिकारी थे ओमप्रकाश

ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और मूल रूप से बिहार के चंपारण जिले से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने भूविज्ञान में एमएससी की पढ़ाई की थी। अपने करियर के दौरान वे कई अहम पदों पर रहे। अग्निशमन दल और होम गार्ड्स के डीजीपी रह चुके। 11 मार्च 2015 को वे कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक बने।

अपने सख्त प्रशासन और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे परिवार संग बैंगलुरु में ही बस गए थे।

पारिवारिक कलह बनी वजह

पुलिस सूत्रों और पड़ोसियों के मुताबिक, पिछले कुछ समय से ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। अक्सर दोनों के बीच बहस और झगड़े होते रहते थे।

पड़ोसियों ने बताया कि हाल ही में घर से जोर-जोर से चिल्लाने और हंगामे की आवाजें भी सुनी गई थीं। कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों को भी पता था कि दंपति के बीच विवाद बढ़ गया है।

जांच अधिकारियों का कहना है कि संभवतः घरेलू



झगड़े ने ही इस दुखद घटना का रूप ले लिया। रविवार शाम झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने गुस्से में आकर पति पर हमला कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, वारदात के बाद उन्होंने मानसिक संतुलन खो देने जैसी स्थिति में पुलिस को खुद फोन कर सूचना दी।

बेटी भी हिंसत में

हत्या के समय घर में दंपति की बेटी भी मौजूद थी। पुलिस ने एहतियातन पत्नी के साथ बेटी को भी हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ से ही स्पष्ट होगा कि वारदात के दौरान बेटी की क्या भूमिका रही थी। वह सिर्फ गवाह थी।

पुलिस अधिकारियों में सदमा

राज्य के पुलिस महकमे और रिटायर्ड अधिकारियों में इस घटना से गहरा सदमा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "राज्य पुलिस विभाग के मुखिया रहे अधिकारी की इस तरह निर्मम हत्या होना वाकई हैरान करने वाला है। हम सब स्तब्ध हैं।" रिटायर्ड अफसरों का कहना है कि वे जानते थे कि दंपति के बीच झगड़े हैं, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था।

एक प्रतिष्ठित करियर का दुखद अंत

ओम प्रकाश को एक कर्मठ और ईमानदार अधिकारी

के रूप में जाना जाता था। उनके साथ काम कर चुके कई अधिकारियों ने उन्हें एक अनुशासित और सरल स्वभाव का इंसान बताया। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहते थे। उनकी हत्या से न केवल पुलिस विभाग, बल्कि पूरा प्रशासनिक और सामाजिक जगत स्तब्ध है।

पड़ोसियों की प्रतिक्रिया

एचएसआर लेआउट के पड़ोसियों का कहना है कि ओम प्रकाश बहुत शांत और सौम्य स्वभाव के थे। "वे सुबह-शाम ठहलने निकलते थे और हर किसी को नमस्ते करते थे। यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके घर से ऐसी खबर आई है," एक पड़ोसी ने कहा।

मानसिक स्वास्थ्य का पहलू

पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी पत्नी पल्लवी मानसिक तनाव और अस्थिरता से जूझ रही थी। पिछले कुछ महीनों में उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। माना जा रहा है कि इसी अस्थिर मानसिक स्थिति ने झगड़े को खतरनाक मोड़ दे दिया।

तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला

यह मामला सिर्फ अपराध की घटना नहीं है, बल्कि

घरेलू तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौतियों को भी उजागर करता है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी, जिसने पूरे जीवन कानून-व्यवस्था को संभाला, उसकी जान पारिवारिक कलह में चली गई। यह घटना बताती है कि रिश्तों में तनाव और संवादहीनता किस तरह एक बड़े संकट का रूप ले सकती है।

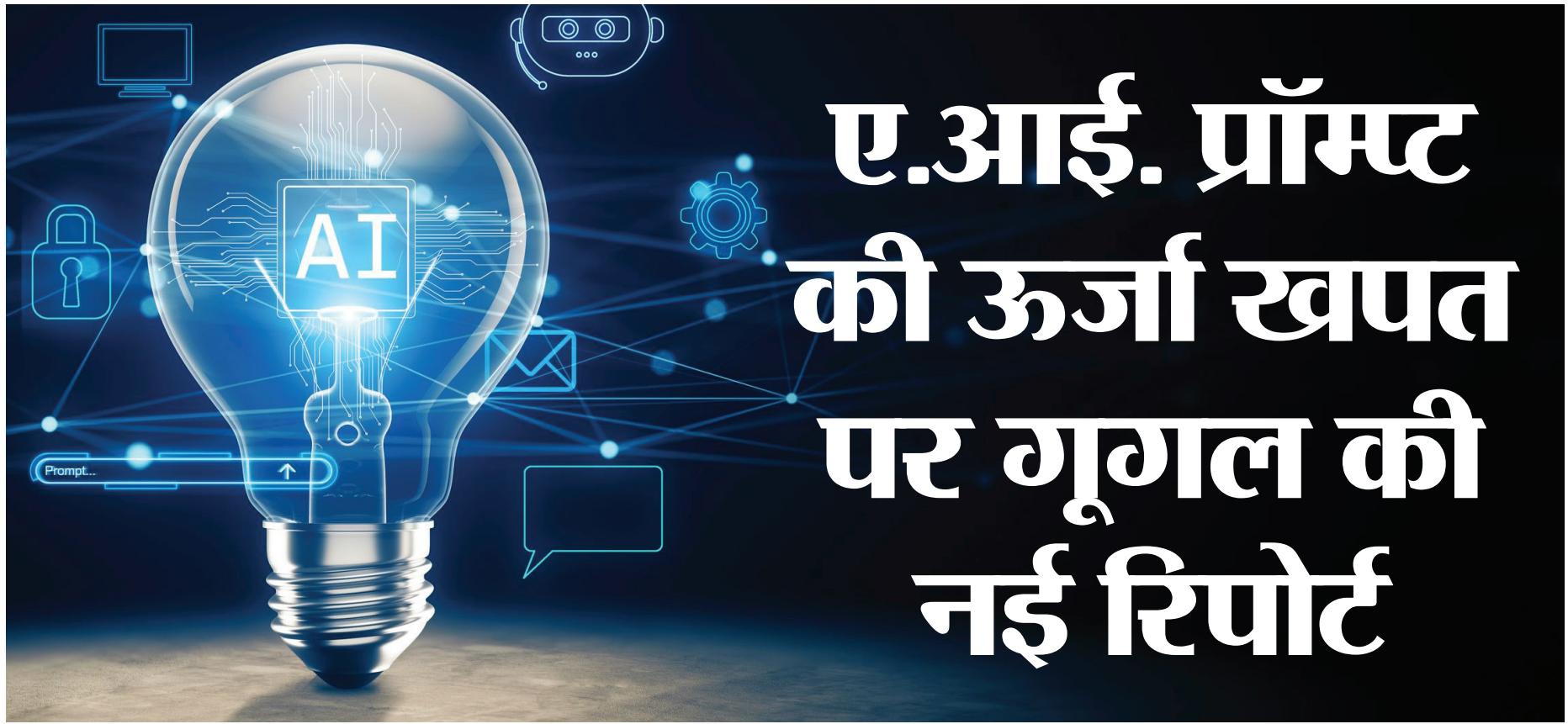
पत्नी और बेटी हिंसत में

फिलहाल पुलिस ने पत्नी और बेटी को हिरासत में लिया है। विस्तृत पूछताछ के बाद ही हत्या की पूरी कहानी सामने आई। पुलिस वारदात में इस्तेमाल हथियार, झगड़े का सिलसिला और घटना के समय की परिस्थितियों की जांच कर रही है।

कई सवाल हैं सामने

ओम प्रकाश की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या समय रहते पारिवारिक विवादों को रोका जा सकता था? क्या मानसिक स्वास्थ्य के संकेतों को परिवार और समाज ने नजरअंदाज किया? और क्या ऐसे मामलों में संस्थागत मदद उपलब्ध है?

कर्नाटक पुलिस विभाग के पूर्व मुखिया ओम प्रकाश की हत्या किसी सामान्य अपराध से कहीं अधिक है। यह एक चेतावनी है कि घरेलू कलह और मानसिक असंतुलन किस तरह बड़े हादसों को जन्म दे सकते हैं।



आ

जकल ए.आई. हर जगह है। फोन से लेकर कंप्यूटर तक, हम रोजाना ए.आई. टूल्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक साधारण सवाल पूछने में कितनी बिजली लगती है? गूगल ने हाल ही में अपनी जेमिनी ए.आई. के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। यह पहली बार है जब कोई बड़ी कंपनी ने इतनी विस्तार से बताया कि ए.आई. प्रॉम्प्ट कितनी ऊर्जा खाता है। रिपोर्ट अगस्त 2025 में आई है। इसमें कहा गया है कि एक औसत टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में 0.24 वाट-घंटा बिजली लगती है। यह इतनी है जितनी एक माइक्रोवेव को एक सेंकंड चलाने में लगती है। पानी की खपत भी बताई गई है – सिर्फ 0.26 मिलीलीटर, यानी पांच बूँदें। कार्बन उत्सर्जन 0.03 ग्राम है। यह रिपोर्ट शोधकर्ताओं के लिए बड़ा खुलासा है। लेकिन क्या यह पूरी तस्वीर दिखाती है? आइए विस्तार से देखें।

यह रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ए.आई. का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लोग चिंता करते हैं कि ए.आई. पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। गूगल ने कहा कि उन्होंने सब कुछ शामिल किया – ए.आई. चिप्स से लेकर डेटा सेंटर के कूलिंग तक। लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि कुल खपत का हिसाब नहीं दिया गया। जैसे, कितने प्रॉम्प्ट रोज आते हैं? अगर अरबों प्रॉम्प्ट हों तो छोटी-छोटी खपत मिलकर बड़ी हो जाती है। फिर भी, यह शुरुआत है। रिपोर्ट से पता चलता है कि तकनीक सुधार रही है। मई 2024 से मई 2025 तक ऊर्जा खपत 33 गुना कम हुई। यह अच्छी खबर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अन्य कंपनियां भी ऐसा करेंगी?

रिपोर्ट क्या कहती है?

रिपोर्ट में गूगल ने जेमिनी ए.आई. के टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पर फोकस किया। जेमिनी गूगल का पॉपुलर ए.आई. टूल है। एक मीडियन प्रॉम्प्ट – यानी बीच वाला, न ज्यादा छोटा न बड़ा – 0.24 वाट-घंटा बिजली इस्तेमाल करता है। यह इतनी ऊर्जा है जितनी टीवी नौ सेकंड चलाने में लगती है। पानी की बात करें तो 0.26 मिलीलीटर। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 ग्राम। गूगल ने बताया कि यह गणना कैसे की। उन्होंने सिर्फ ए.आई. चिप्स नहीं, बल्कि पूरी

सिस्टम को देखा।

ब्रेकाउन देखें। 58 प्रतिशत ऊर्जा ए.आई. चिप्स (टीपीयू) पर जाती है। ये गूगल के खुद के चिप्स हैं, जीपीयू जैसे। 25 प्रतिशत होस्ट मशीन के सीपीयू और मेमोरी पर। 10 प्रतिशत बैकअप मशीनों पर, जो खाली रहती हैं ताकि कोई समस्या हो तो काम चले। 8 प्रतिशत डेटा सेंटर के ओवरहेड पर, जैसे कूलिंग और पावर कन्वर्शन। यह व्यापक नजरिया है। अन्य स्टडीज में सिर्फ चिप्स की बात होती है, जो 0.10 वाट-घंटा दिखाती है। लेकिन गूगल कहता है कि असली खपत ज्यादा है क्योंकि सपोर्ट सिस्टम को शामिल करना जरूरी।

यह सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए है। इमेज या वीडियो बनाने में ज्यादा ऊर्जा लगती है। जैसे, दर्जनों किताबें डालकर सारांश मांगो तो ज्यादा बिजली जाएगी। रिजनिंग मॉडल्स भी ज्यादा स्टेप्स लेते हैं, इसलिए ज्यादा खपत। गूगल ने कार्बन उत्सर्जन की गणना मार्केट-बेस्ड तरीके से की। मतलब, उन्होंने अपनी क्लीन एनर्जी खरीद को घटाया। गूगल ने 2010 से 22 गीगावाट क्लीन पावर खरीदा है – सोलर, विंड, जियोथर्मल। इसलिए उनके उत्सर्जन प्रिड औसत से एक-तिहाई कम है। लेकिन कुछ कहते हैं कि लोकेशन-बेस्ड हिसाब बेहतर, क्योंकि असली प्रिड अभी क्लीन नहीं।

रिपोर्ट से एक बात साफ है। ए.आई. की खपत रोजमरा की चीजों जैसी है। जैसे, पांच बूँद पानी या कुछ सेकंड टीवी। गूगल के चीफ साइंटिस्ट जेफ डीन कहते हैं कि लोग बिना सोचे ऐसी चीजें करते हैं। तो ए.आई. से चिंता क्यों? लेकिन अगर यूजर्स अरबों हैं तो कुल खपत बड़ी हो सकती है। गूगल ने कुल क्वेरी नंबर नहीं बताया। यह कमी है। फिर भी, यह रिपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मिसाल है।

सुधार और तकनीकी बदलाव

गूगल ने दिखाया कि ए.आई. कितनी तेज सुधार रही है। मई 2024 से मई 2025 तक मीडियन प्रॉम्प्ट की ऊर्जा खपत 33 गुना कम हुई। कार्बन फुटप्रिंट 44 गुना कम। यह कैसे? मॉडल ऑटोमेइजेशन से। सॉफ्टवेयर बेहतर बना। हार्डवेयर इफिशिएंट। मशीन यूटिलाइजेशन बढ़ा। क्लीन एनर्जी ज्यादा खरीदी। और रिस्पॉन्स क्वालिटी कैसे की। उन्होंने सिर्फ ए.आई. चिप्स नहीं, बल्कि पूरी

ए.आई. प्रॉम्प्ट की ऊर्जा खपत पर गूगल की नई रिपोर्ट

भी बेहतर हुई।

उदाहरण लें। पहले मॉडल्स ज्यादा स्टेप्स लेते थे। अब स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। हाइब्रिड रीजनिंग, डिस्टिलेशन – बड़े मॉडल्स छोटों को सिखाते हैं। कस्टम हार्डवेयर जैसे टीपीयू। डेटा सेंटर में कूलिंग बेहतर। गूगल का पावर यूसेज इफेक्टिवनेस (पीयूर्ड) कम हो रहा है। यह सब मिलकर खपत घटाती है।

लेकिन क्या यह काफी? कुछ विशेषज्ञ जेवन्स पैराडॉक्स की बात करते हैं। मतलब, इफिशिएंसी बढ़ने से यूज बढ़ जाता है। खपत कम नहीं होती। गूगल के कुल उत्सर्जन 2019 से 48 प्रतिशत बढ़े। डेटा सेंटर एनर्जी डबल हुई चार साल में। ए.आई. बूम से डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं। कुछ 100 से 1000 मेगावाट लेते हैं – 80,000 घरों जितनी बिजली। लेकिन गूगल कहता है कि वे क्लीन एनर्जी पर फोकस कर रहे। 24/7 मैचिंग – हर घंटे क्लीन पावर। यह अन्य कंपनियों से अगे है।

ओपनए.आई. ने जून में कहा कि चैटजीपीटी प्रॉम्प्ट 0.34 वाट-घंटा लेता है। मिस्ट्रल का ले चैट ज्यादा पानी लेता है – 50 मिलीलीटर। लेकिन गूगल की मेथड ज्यादा कंप्रीहेंसिव। ड्रेनिंग एनर्जी नहीं शामिल। ड्रेनिंग में गीगावाट-घंटा लगता है। लेकिन इंफरेंस (प्रॉम्प्ट) रोजाना होता है, इसलिए ज्यादा इंपैक्ट। कुल मिलाकर, तकनीक सुधार रही है। लेकिन स्केल बड़ा सवाल है।

विशेषज्ञों और उपयोगकर्ताओं की राय

यह रिपोर्ट आई तो प्रतिक्रियाएं मिली-जुली। शोधकर्ता खुश हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोशारफ चौधरी कहते हैं कि यह कीस्टोन पीस है। कंपनियां ही असली डेटा दे सकती हैं। हांगिंग फेस की साशा लुच्चियोनी कहती हैं कि अच्छा है, लेकिन कुल क्वेरी नंबर न होने से कुल इंपैक्ट पता नहीं। वे ए.आई. एनर्जी स्कोर की मांग करती हैं – जैसे एनर्जी स्टार रेटिंग।

एक विचार: ए.आई. एनर्जी स्कोर हो। यूजर्स चुनें कि कौनसा मॉडल इस्तेमाल करें। या गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट करें क्लीन टेक में। ए.आई. खुद सॉल्यूशन दे सकता है – बेहतर एनर्जी मैनेजमेंट। लेकिन अभी सवाल ज्यादा। क्या ए.आई. स्टेटेनेबल बनेगा? या बोझ? यह हम पर निर्भर। रिपोर्ट पढ़ें, सोचें। छोटी खपत मिलकर बड़ी हो सकती है। लेकिन सुधार से उम्मीद है।

लगता है, लेकिन गूगल ने रीप्लेनिशेमेंट का वादा किया। क्रिटिक्स कहते हैं कि ट्रेनिंग को छिपाया। रेडिट पर एक थ्रेड में कहा गया कि 100 प्रॉम्प्ट रोज तो छोटी बात नहीं।

बैलेस्ड व्यू: ट्रांसपरेंसी अच्छी। लेकिन स्टैंडार्ड से ज़रूरी। सरकारें रिपोर्टिंग अनिवार्य करें? या कंपनियां खुद करें? जोफ डीन कहते हैं कि यूजर्स को पता चले कि उनका इंटरैक्शन कितना इंपैक्ट करता है। लेकिन आर अरबों यूजर्स तो कुल बिजली बड़ी। कुछ कहते हैं कि ए.आई. ग्रोथ से एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इफिशिएंसी बचा सकती है। मिशिगन के जे-वॉन चुंग कहते हैं कि यह सबसे कंप्रीहेंसिव एनालिसिस है। लेकिन इंडस्ट्री इनपुट के बिना रिसर्च मुश्किल।

यूजर्स की राय: कुछ कहते हैं कि ए.आई. वैल्यूफुल है, खपत छोटी। जैसे, एक प्रॉम्प्ट से घंटों का काम बचता है। लेकिन पर्यावरणवादी चिंतित। ए.आई. बूम से डेटा सेंटर बढ़ रहे, ग्रिड पर बोझ। बैलेस्ड चाहिए।

आगे की चुनौतियां और विचार

यह रिपोर्ट एक कदम है, लेकिन रोड लंबा। ए.आई. का पर्यावरण क्या? ज्यादा मल्टीमोडल – इमेज, वीडियो। इनमें ज्यादा एनर्जी। ड्रेनिंग का इंपैक्ट बड़ा। कंपनियां डेटा छिपाती हैं क्योंकि ड्रेड सीक्रेट। लेकिन प्रेशर बढ़ रहा। रेगुलेशंस आ सकते हैं। जैसे, एनर्जी डिस्कलोजर अनिवार्य।

सोचिए। ए.आई. जीडीपी बढ़ाएगा – गोल्डमैन सैक्स कहता है 7 प्रतिशत। लेकिन पर्यावरण कॉस्ट? क्या हम तैयार? गूगल जैसे सुधार दिखाते हैं कि संभव है। लेकिन कुल यूज बढ़ेगा। जेवन्स पैराडॉक्स याद रखें। इफिशिएंसी से यूज बढ़ता है। क्या क्लीन एनर्जी काफी? गूगल 24/7 मैचिंग कर रहा, लेकिन पूरी इंडस्ट्री नहीं।

एक विचार: ए.आई. एनर्जी स्कोर हो। यूजर्स चुनें कि कौनसा मॉडल इस्तेमाल करें। या गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट करें क्लीन टेक में। ए.आई. खुद सॉल्यूशन दे सकता है – बेहतर एनर्जी मैनेजमेंट। लेकिन अभी सवाल ज्यादा। क्या ए.आई. स्टेटेनेबल बनेगा? या बोझ? यह हम पर निर्भर। रिपोर्ट पढ़ें, सोचें। छोटी खपत मिलकर बड़ी हो सकती है। लेकिन सुधार से उम्मीद है।

उकता कर कई बार
सोचता उठ जाये यहाँ से
लेकिन सुना है
कुछ अच्छों के होने से ही
यह दुनिया है
यही सोचकर
रह जाता उस ओर

इतना है भार
इधर जरा कम होते जौर
गाड़ी कर्णी हो न जाये उलार

अच्छा है
कि अच्छे आदमी को पता है
उसके होने का मतलब क्या है

दुनिया को देखता वरु
किसी बूढ़े बच्चे की तरह
जिसे छोड़ कर
घर के बाकी सब निकल गये हैं बाहर ...

प्रेम रंगन अनिमेष

माँ के लिए संभव नहीं होगी मुझसे कविता
अमर विंडियों का एक दस्ता
मेरे मस्तिष्क में रेंगता रहता है
माँ वर्ण लर रोज दुटकी दो दुटकी आठा डाल देती है

मैं जब भी सोचना शुरू करता हूँ
यह किस तरह होता होगा
घंटी पीसने की आवाज
मुझे धेरने लगती है
और मैं बैठे-बैठे दूसरी दुनिया में ऊँधने लगता हूँ

जब कोई भी माँ छिलके उतारकर
चने, मूँगफली या भट्टर के दाने
नहीं ठेलियों पर रख देती है

तब मेरे गाथ अपनी जगह पर
थरथराने लगते हैं
माँ ने छर चीज़ के छिलके उतारे मेरे लिए
देन, आत्मा, आग और पानी तक के छिलके उतारे
और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया

मैंने धरती पर कविता लिखी है
घंटमा को गिटार में बदला है
सनुद को शर की तरह आकाश के पिंजरे में खड़ा
कर दिया
सूरज पर कभी भी कविता लिख दूँगा
माँ पर नहीं लिख सकता कविता।

चब्दकान्त देवताले

एक भाषा में अ लिखना चाहता हूँ
अ से अनार अ से अमरुद
लेकिन लिखने लगता हूँ अ से अनर्थ अ से अत्याधार
कौशिश करता हूँ कि क से कलम या करुणा लिखें
लेकिन मैं लिखने लगता हूँ क से कूरता क से कुटिलता
अभी तक यह से खरगोश लिखता आया हूँ
लेकिन यह से अब किसी खतरे की आलट आने लगी है
मैं सोचता था कि क से फूल ही लिखा जाता होगा
बहुत सारे फूल
घरों के बाहर घरों के भीतर मनुष्यों के भीतर
लेकिन मैंने देरवा तमाम फूल जा रहे थे
जालिमों के गले में माला बन कर डाले जाने के लिए

कोई मेरा गाथ जकड़ता है और कहता है
म से लिखो भय जो अब लर जगह मौजूद है
द दमन का और प यतन का सँकेत है
आतायी छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला
वे भाषा की हिंसा को बना देते हैं
समाज की हिंसा
ह को रुत्या के लिए सुरक्षित कर दिया गया है
ठम कितना ही लल और हिरन लिखते रहें
वे ह से रुत्या लिखते रहते हैं रुर समय।

मंगलेश उबरात

एक इंडियन ड्राइवर के हादसे ने हिला दी अमेरिका की वीजा पॉलिसी



@ अंकित कुमार

अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच जोरदार बहस छिड़ गई है और डोनाल्ड ट्रंप पर अवैध घुसपैठियों को लाइसेंस देने का आरोप लगाया जा रहा है। गाड़ी चला रहे इस भारतीय पंजाबी शख्स पर आरोप है कि उसने अमेरिका में पहले अवैध घुसपैठ की ओर फिर वहां एक कमर्शियल ड्राइवर बन गया। सड़क पर उसने एक गलत यूटर्न की वजह से भयानक हादसा हो गया और तीन अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई है।

फ्लोरिडा में गलत तरीके से हाईवे पर यूटर्न ले रहे एक ट्रक से तेज रफ्तार कार भिड़ जाती है। टक्कर इतनी तेज होती है कि हादसे में कार सवार तीन अमेरिकी नागरिकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसका वीडियो ट्रक के डैश कैम में लगे कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता है। वीडियो में ट्रक चलाते हुए दिख रहे शख्स की पहचान हरजिंदर सिंह के तौर पर होती है जो कि भारत का नागरिक है। पूछताछ में पता चलता है कि साल 2018 में वह साउथ बॉर्डर को अवैध तरीके से पार कर अमेरिका में घुसा था। साउथ बॉर्डर यानी मेक्सिको वाला बॉर्डर। अमेरिकी अदालत में उसने अमेरिका में शरण देने की मांग की थी। यह बताकर कि भारत में उसकी जान को खतरा है। अमेरिका में शरण लेने वाले अवैध प्रवासियों के लिए जान को खतरा बताना सबसे कॉमन दलील होती है।

यहां तक आपको एक्सीडेंट का वाक्या बता दिया। अब यह बताते हैं कि कैसे इस एक्सीडेंट की वजह से अमेरिका को अपनी वीजा पॉलिसी बदलनी पड़ गई है। कैसे विदेशी ड्राइवर्स को लेकर बहस छिड़ गई है और कैसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल एक्सीडेंट फ्लोरिडा में हुआ था। ऐसे में केस भी फ्लोरिडा में ही चलना है। लेकिन हरजिंदर कैलिफोर्निया स्टेट तो उसके खिलाफ केस चलाने और उसे सजा देने में मदद कर रहा है। उन्होंने तुरंत ही उसके फ्लोरिडा प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है।

वैसे तो अमेरिका में आए दिन विदेशी ड्राइवर्स के मुद्दे पर हंगामा होता रहता है और ट्रंप प्रशासन या उनकी पार्टी रिपब्लिकन हमेशा से प्रवासियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाती है। अब फ्लोरिडा के हादसे के पीछे का जिम्मेदार एक विदेशी ड्राइवर को ठहराया जा रहा है। लेकिन असल

हंगामा है उसके कैलिफोर्निया स्टेट का निवासी होने के चलते। कैलिफोर्निया में ट्रंप की प्रतिद्वंदी पार्टी डेमोक्रेट्स का कंट्रोल है और डेमोक्रेट्स हमेशा से ही ट्रंप के इमीग्रेशन पर की गई कारवाइयों का विरोध करता है। जबकि फ्लोरिडा अभी ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के कंट्रोल में है।

ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने इस हादसे को जोरों शोरों से उठाया और इसका जिम्मेदार कैलिफोर्निया स्टेट के गवर्नर गेविन नसोम को बताया है। आरोप लगाया है कि डेमोक्रेट्स के कंट्रोल वाले कैलिफोर्निया से ही विदेशी मूल के हरजिंदर को कमर्शियल लाइसेंस मिला था। जिसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते तीन अमेरिकी नागरिकों की जान चली गई है ऐसे में डेमोक्रेट्स ने इसका पलटवार किया। गवर्नर गेविन के ऑफिस ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि ट्रंप की ही संघीय सरकार ने हरजिंदर को अमेरिका में वर्क परमिट जारी किया था, ना कि डेमोक्रेट्स ने। जबकि कैलिफोर्निया स्टेट तो उसके खिलाफ केस चलाने और उसे सजा देने में मदद कर रहा है। उन्होंने तुरंत ही उसके फ्लोरिडा प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है।

राजनीति चलती रहेगी। जानना यह जरूरी है कि अमेरिका ने वीजा पॉलिसी में क्या बदलाव किए हैं। अमेरिका ने सभी विदेशी ट्रक ड्राइवर्स के लिए वीजा जारी करना बंद कर दिया है। टोटल शटडाउन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 21 अगस्त को इसकी घोषणा की है। एक्स पर मार्को रूबियो ने लिखा है कि अमेरिकी सड़कों पर बड़े-बड़े ट्रेलर ट्रैक्टर चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की

बढ़ती संख्या अमेरिकी जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक ड्राइवर्स की आजीविका को भी कम कर रही है। हम तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर वीजा जारी करने पर रोक लगा रहे हैं। पहले भी कई रिपब्लिकन सांसद विदेशी ट्रक ड्राइवर्स पर निशाना साथ चुके हैं। उनका दावा है कि इनकी वजह से अमेरिका में हादसों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि अपने दावों के लिए वह कोई ठोस सबूत आज तक पेश नहीं कर पाए।

अभी वीजा बैन लगने से पहले जून 2025 में अमेरिकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सीन डफी ने निर्देश दिया था कि अमेरिका में ट्रक चलाने वाले सभी ड्राइवर्स को अंग्रेजी बोलना होगा। यह अनिवार्य है बता दें अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स को कमर्शियल लाइसेंस पाने के लिए एजाम देना होता है। जिसमें अंग्रेजी की समझ और सड़क पर मौजूद संकेतों की बुनियादी समझ जरूरी होती है। साल 2016 में डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा प्रशासन ने इन नियमों को रद्द कर दिया था। तर्क दिया था कि भाषा की कमी के आधार पर सड़क से ड्राइवर्स को नहीं हटाया जा सकता। डाटा के मुताबिक साल 2000 से 2021 के बीच अमेरिका में विदेशी मूल्य के ट्रक ड्राइवर्स की संख्या दोगुनी से भी अधिक होकर 7200 के पार चली गई थी। ये ड्राइवर्स अब भी अमेरिकी श्रम उद्योगों में काम कर रहे हैं। इनमें आधे से ज्यादा ड्राइवर्स लैटिन अमेरिका से हैं। जबकि हाल के सालों में भारत या पूर्वी यूरोपियन देशों से आने वाले ड्राइवर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है।

भारत के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति अमीरी और गरीबी की कहानी

भा

रत जैसे बड़े देश में राजनीति करने वाले लोग अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। कुछ नेता बहुत अमीर होते हैं, तो कुछ सादा जीवन जीते हैं। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की एक संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के बारे में बताया गया है। यह जानकारी चुनाव के समय भरे गए हलफनामों से ली गई है। रिपोर्ट कहती है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर हैं। उनकी संपत्ति 931 करोड़ रुपये से ज्यादा है। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे गरीब हैं। उनकी संपत्ति सिर्फ 15 लाख रुपये के आसपास है।

यह फर्क देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। अमीर नेता कैसे इतनी संपत्ति बनाते हैं? गरीब नेता कैसे सादा जीवन जीते हैं? क्या संपत्ति का राजनीति से कोई संबंध है? रिपोर्ट 2024 के चुनावों के बाद आई है, और यह 2025 तक की ताजा है। एक तरफ अमीरों के फायदे हैं, दूसरी तरफ सादी की मिसाल। चलिए, विस्तार से जानते हैं।

कुल मिलाकर, देश के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 52 करोड़ रुपये से ज्यादा है। लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। 931 करोड़ से 15 लाख तक। यह अंतर हमें समाज की असमानता याद दिलाता है।

चंद्रबाबू नायडू: देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री

चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वे तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं। 2024 के चुनावों में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन उनकी संपत्ति की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपये से अधिक है। यह रकम बहुत बड़ी है। देश के बाकी मुख्यमंत्रियों में कोई उनके करीब भी नहीं है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं, जिनकी संपत्ति 332 करोड़ रुपये है।

नायडू का जन्म 1950 में हुआ था। वे चित्तूर जिले के एक गांव से हैं। राजनीति में आने से पहले वे व्यापार में थे। उन्होंने कई कंपनियां शुरू कीं। कुछ असफल रहीं, लेकिन एक सफल हुई। वे कहते हैं कि वे उद्यमी हैं। राजनीति उनके लिए सेवा है। लेकिन उनकी अमीरी पर सवाल भी उठते हैं। विपक्ष कहता है कि राज्य कर्ज में डूबा है, लेकिन मुख्यमंत्री अमीर हो रहे हैं। नायडू इसका जवाब देते हैं कि उनकी संपत्ति पारदर्शी है। सब चुनावी हलफनामे में लिखा है।

उनकी संपत्ति में चल और अचल दोनों शामिल हैं। लेकिन मुख्य हिस्सा शेरयों से है। वे परिवार के साथ मिलकर कंपनियां चलाते हैं। उनकी पत्नी भुवनेश्वरी और बेटा लोकेश भी शामिल हैं। कुल मिलाकर, नायडू परिवार की संपत्ति राजनीति और व्यापार का मिश्रण है। लेकिन क्या यह गलत है? नहीं, अगर सब कानूनी हो। कई लोग कहते हैं कि अमीर नेता विकास ला सकते हैं।

वे व्यापार जानते हैं। नायडू ने आंध्र प्रदेश को आईटी हब बनाने की कोशिश की। अमरावती शहर की जोन उनकी थी। लेकिन विपक्ष कहता है कि अमीरी से भ्रष्टाचार जुड़ सकता है। संतुलन जरूरी है। नायडू की संपत्ति साल दर साल बढ़ी है। 2019 में कम थी, अब ज्यादा। शेरयर बाजार से फायदा हुआ। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि वे मुख्यमंत्री अरबपति हैं। नायडू और खांडू बाकी औसत से कम। यह दिखाता है कि राजनीति में अमीर और गरीब दोनों हैं। नायडू का उदाहरण हमें बताता है कि व्यापार और राजनीति साथ चल सकते हैं। लेकिन पारदर्शिता जरूरी है।

पैसे का मुख्य स्रोत: हेरिटेज फूड्स की कहानी

चंद्रबाबू नायडू की अमीरी का बड़ा हिस्सा हेरिटेज फूड्स से आता है। यह एक डेयरी कंपनी है। उन्होंने 1992 में इसे शुरू किया। शुरुआत छोटी थी। सिर्फ 4 करोड़ रुपये का कारोबार। लेकिन अब सालाना 5000 करोड़ से ज्यादा। कंपनी दूध, दही, आइसक्रीम बेचती है। 12 राज्यों में फैली है।

कंपनी का उद्देश्य किसानों की मदद था। नायडू कहते हैं कि वे किसानों को सशक्त बनाना चाहते थे। बीच के दलालों को हटाकर सीधे किसानों से दूध खरीदते हैं। लाखों किसान जुड़े हैं। कंपनी पब्लिक है। शेरयर बाजार में लिस्टेड। नायडू के पास 24 प्रतिशत शेरयर हैं। उनकी पत्नी के पास भी इतने ही। चुनाव जीतने के बाद शेरयर दोगुने हो गए। परिवार की संपत्ति 1200 करोड़ बढ़ी।

हेरिटेज की शुरुआत से पहले नायडू ने तीन कंपनियां बंद कीं। चौथी सफल हुई। वे कहते हैं कि असफलता से सीखा। कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी है। लेकिन मुख्य व्यापार डेयरी है। 15 प्लांट हैं। रोज 14 लाख लीटर दूध संभालते हैं। लक्ष्य 32 लाख लीटर।

क्या यह स्रोत सही है? हां, क्योंकि कंपनी कानूनी है। लेकिन सवाल है कि राजनीति में रहते हुए व्यापार कैसे? नायडू कहते हैं कि पत्नी और बहू, संभालती हैं। वे सिर्फ संस्थापक हैं। वे प्रकृति के लिए कानूनी हैं। लेकिन कहते हैं कि अमीर नेता विकास ला सकते हैं।

फायदा राजनीति से मिला। जैसे, चुनाव जीतने पर शेरयर बढ़े। लेकिन बाजार ऐसा ही है। संतुलित नजर से देखें तो यह सफल उद्यमी की कहानी है। किसानों को फायदा हुआ। रोजगार मिला। लेकिन अमीरी का फर्क समाज में असमानता बढ़ाता है। अब सबसे गरीब मुख्यमंत्री पर बात।

सबसे गरीब मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी की सादगी और जीवनशैली

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। उनकी संपत्ति सिर्फ 15 लाख रुपये है। इसमें नकद 69 हजार, बैंक में 13 लाख, कुछ गहने और टीटीडीएस शामिल हैं। कोई जमीन या घर नहीं। 2021 के चुनाव में यह बताया। अब भी वही। पहले 30 लाख थी, अब कम।

ममता की जीवनशैली बहुत सादा है। वे कोलकाता की एक गली में छोटे घर में रहती हैं। कोई लग्जरी नहीं। सामाजिक कार्य और राजनीति उनकी कमाई है। सालाना

आय 15 लाख। वे कहती हैं कि जनता के लिए

सब त्याग दिया। कोई नहीं।

वे क्या सादी अच्छी है? हां, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं। लेकिन अमीर नेता कहते हैं कि विकास के लिए पैसा जरूरी। ममता का उदाहरण बताता है कि बिना अमीरी के भी सेवा हो सकती है। दूसरे गरीब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास 55 लाख, पिनाराइ विजयन के पास 1 करोड़। लेकिन ममता सबसे नीचे। यह सोचने लायक है।

अमीरी और गरीबी का फर्क: राजनीतिपर क्या असर

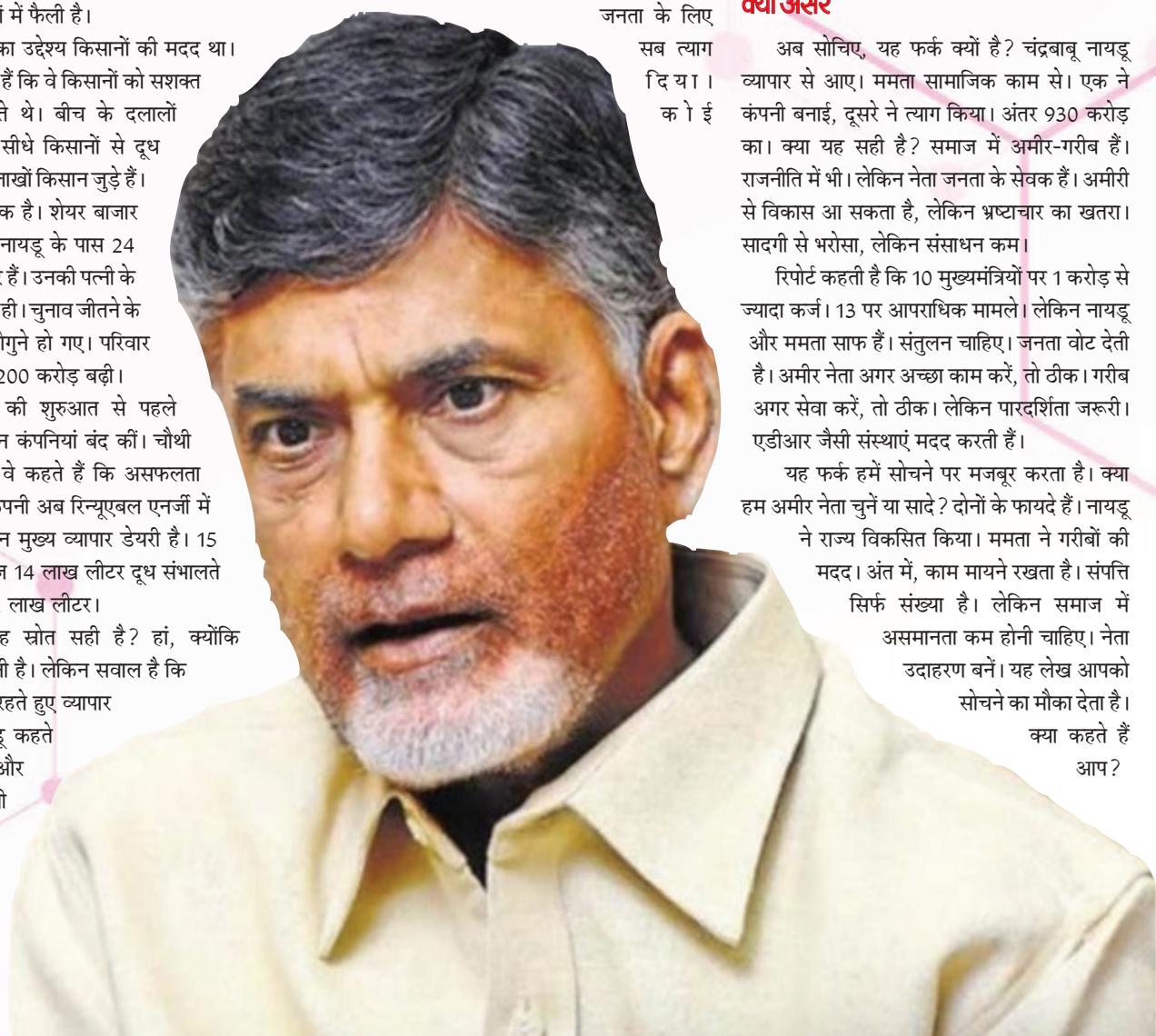
अब सोचिए, यह फर्क क्यों है? चंद्रबाबू नायडू व्यापार से आए। ममता सामाजिक काम से। एक ने कंपनी बनाई, दूसरे ने त्याग किया। अंतर 930 करोड़ का। क्या यह सही है? समाज में अमीर-गरीब हैं। राजनीति में भी। लेकिन नेता जनता के सेवक हैं। अमीरी से विकास आ सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार का खतरा। सादगी से भरोसा, लेकिन संसाधन कम।

रिपोर्ट कहती है कि 10 मुख्यमंत्रियों पर 1 करोड़ से ज्यादा कर्ज। 13 पर आपराधिक मामले। लेकिन नायडू और ममता साफ हैं। संतुलन चाहिए। जनता बोट देती है। अमीर नेता अगर अच्छा काम करें, तो ठीक। गरीब अगर सेवा करें, तो ठीक। लेकिन पारदर्शिता जरूरी। एडीआर जैसी संस्थाएं मदद करती हैं।

यह फर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अमीर नेता चुनें या सादे? दोनों के फायदे हैं। नायडू ने राज्य विकसित किया। ममता ने गरीबों की मदद। अंत में, काम मायने रखता है। संपत्ति सिर्फ संख्या है। लेकिन समाज में

सिर्फ संस्थाएं मदद करती हैं। नेता उदाहरण बनें। यह लेख आपको सोचने का मौका देता है।

क्या कहते हैं आप?



टिकटॉक की भारत में वापसी: अफवाह या हकीकत?

आ

जकल सोशल मीडिया पर एक नाम फिर से चर्चा में है – टिकटॉक। पांच साल पहले, जून 2020 में भारत सरकार ने इस चीनी एप को बैन कर दिया था। वजह थी राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी की चिंता। उस समय भारत-चीन सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ था। टिकटॉक के अलावा 58 अन्य चीनी एप्स पर भी रोक लगी। लेकिन अब, अगस्त 2025 में, कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि टिकटॉक की वेबसाइट भारत में खुल रही है। क्या ये वापसी का संकेत है? या सिर्फ एक गड़बड़ी?

टिकटॉक एक छोटे वीडियो बनाने वाला एप था। इसमें लोग गाने पर डांस करते, कॉमेडी करते या अपनी जिंदगी की छोटी-छोटी बातें शेयर करते थे। भारत में इसके 200 मिलियन से ज्यादा यूजर्स थे। बैन के बाद, कई लोग उदास हुए। लेकिन समय के साथ, दूसरे एप्स ने उसकी जगह ले ली। जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉट्स, मोज और जोश। अब सवाल ये है कि क्या टिकटॉक फिर से भारतीयों के फोन में जगह बना पाएगा?

पहले जानते हैं कि टिकटॉक क्यों इतना पॉपुलर था। गांव-शहर हर जगह लोग इसका इस्तेमाल करते थे। कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के टिप्प शेयर करता, कोई किसान अपनी फसल की कहानी बताता। लेकिन बैन ने सब बदल दिया। अब अफवाहें फैल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वेबसाइट खुल रही है, तो क्या ऐप भी आएगा? सरकार और कंपनी दोनों ने इनकार किया है। लेकिन क्यों ये अफवाहें फैलीं?

हाल की खबरें और सरकारी बयान

अगस्त 2025 में, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कई यूजर्स ने बताया कि टिकटॉक की आधिकारिक वेबसाइट भारत में बिना वीपीएन के खुल रही है। कुछ ने स्क्रीनशॉट शेयर किए। एक यूजर ने लिखा, “टिकटॉक वापस आ रहा है?” ट्रिवटर (अब एक्स) पर #TikTokIndia ट्रेंड करने लगा। लेकिन ये कितनी सच्चाई है? हमने इंटरनेट सर्च किया। पता चला कि 22 अगस्त को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि वेबसाइट पारिशयल रूप से है। होमपेज खुलता है, लेकिन न्यूजरूम या करियर सेक्शन पर क्लिक करने पर मैसेज आता है – “हमारी सेवाएं आपके देश या क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं।”

टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडॉंस ने बयान दिया। उनके प्रवक्ता ने कहा, “हमने भारत में टिकटॉक तक पहुंच बहाल नहीं की है और भारत सरकार के निर्देश का पालन कर रहे हैं।” ये बयान कई न्यूज साइट्स पर आया। सरकार की तरफ से भी स्पष्टिकरण आया। आईटी मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशल ने कहा कि बैन अभी भी लगा है। सेक्शन 69ए के तहत कोई अनब्लॉकिंग ऑर्डर नहीं जारी हुआ। सरकारी सूत्रों ने कहा, “भारत सरकार ने टिकटॉक के लिए कोई अनब्लॉकिंग ऑर्डर जारी नहीं किया है। ऐसी कोई खबर या बयान गलत और भ्रामक है।”

क्यों वेबसाइट खुली? विशेषज्ञ कहते हैं कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आईएसपी) की गड़बड़ी हो सकती है। 2022 में भी ऐसा हुआ था, जब कुछ यूजर्स को गलती से एक्सेस मिला। लेकिन ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और ऐप्ल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। कोई नया अकाउंट नहीं बन सकता, वीडियो नहीं देख सकता। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में लोग उत्साहित दिखे, लेकिन ज्यादातर ने इसे अफवाह कहा। एक पोस्ट में लिखा, “टिकटॉक वापस? लेकिन सरकार कह रही है फेक न्यूज़।”



पहले भी वापसी की बातें हुईं। मई 2025 में रिपोर्ट्स आईं कि बाइटडॉंस भारतीय पार्टनर ढूँढ़ रही है, जैसे हिरानंदानी ग्रुप। वे डेटा स्टोरेज के नियमों का पालन करके वापस आना चाहते हैं। लेकिन सरकार से कोई हरी झंडी नहीं मिली। भारत-चीन रिश्ते सुधर रहे हैं, पीएम मोदी की चीन यात्रा की चर्चा है, लेकिन बैन पर कोई बदलाव नहीं। सुरक्षा अब भी प्राथमिकता है। क्या ये अफवाहें सिफर्लोगों की उमीद हैं? या कुछ बड़ा होने वाला है? सोचिए, अगर बैन नहीं हटा तो क्यों इतनी चर्चा?

ये मामला सिर्फ एक एप का नहीं। ये डिजिटल सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से जुड़ा है। टिकटॉक के बैन से भारतीय एप्स को फायदा हुआ। लेकिन अगर वापस आया तो बाजार बदल सकता है।

अगर टिकटॉक वापस आया तो क्या होगा?

मान लीजिए टिकटॉक की वापसी हो गई। क्या सब कुछ पहले जैसा होगा? शायद नहीं। पांच साल में बहुत कुछ बदल गया। सबसे पहले, नियम। भारत सरकार ने कहा था कि यूजर डेटा भारत में ही स्टोर होना चाहिए। चीनी सर्वसंपर्क नहीं। टिकटॉक को ये साबित करना होगा कि वो सुरक्षित है। बाइटडॉंस ने पहले कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। अब अगर पार्टनरशिप से आया, जैसे लोकल कंपनी के साथ, तो शायद मंजूरी मिले। लेकिन ये आसान नहीं। अमेरिका में भी टिकटॉक पर बहस चल रही है। भारत ने पहले बैन किया, दुनिया ने देखा।

क्रिएटर्स के लिए क्या? टिकटॉक पर रीच बहुत अच्छी थी। एक वीडियो रातोंत वायरल हो जाता। लेकिन अब इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉट्स पर लाखों क्रिएटर्स हैं। अगर टिकटॉक आया तो नई संभावनाएं आएंगी। ज्यादा कमाई, नए ऑडियंस। लेकिन चुनौती भी। पुराने यूजर्स वापस आएंगे? या नए ऐप्स से चिपके रहेंगे? एक रिपोर्ट कहती है कि टिकटॉक की वापसी से बाजार में हलचल मचेगी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब को कंपटीशन मिलेगा। लेकिन टिकटॉक पर वायरल होना आसान। लोग अब डेटा प्राइवेसी पर ज्यादा सोचते हैं।

समाज पर असर। टिकटॉक पर अच्छा कंटेंट था, लेकिन क्रिंज और फेक न्यूज भी। बैन के बाद, इंस्टाग्राम रील्स पर वैसा ही देखा जाता है। अगर वापस आया तो मॉडरेशन बेहतर होना चाहिए। गांव के लोग, जो टिकटॉक से फेमस हुए, वो खुश होंगे। लेकिन क्या ये देश के लिए अच्छा? चीन से रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का सवाल बाकी। क्या हम चीनी ऐप पर भरोसा करें? या लोकल ऐप्स को सपोर्ट करें? ये सोचने वाली बात है। कोई कहता है कि कंपटीशन से क्वालिटी बढ़ेगी। कोई कहता है कि रिस्क ज्यादा।

अर्थव्यवस्था का पक्ष। टिकटॉक के बैन से भारतीय स्टार्टअप्स उधरे। मोज और जोश ने करोड़ों कमाए। अगर टिकटॉक आया तो नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन लोकल कंपनियां प्रभावित होंगी। एक स्टॉटी कहती है कि टिकटॉक की वापसी से शॉट वीडियो मार्केट और बड़ा होगा। लेकिन क्या भारत तैयार है? एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “टिकटॉक वापस तो क्रिएटर्स के लिए अच्छा, लेकिन सिक्योरिटी?” विचार कीजिए, क्या हम बदलाव चाहते हैं या स्थिरता?

इंस्टाग्राम रील्स से मुकाबला: कोने जीतेगा?

अब मुख्य सवाल – अगर टिकटॉक आया तो इंस्टाग्राम रील्स को पीछे छोड़ देगा? इंस्टाग्राम रील्स टिकटॉक के बैन के बाद आया। अब ये भारत में सबसे पॉपुलर है। करोड़ों यूजर्स रोज रील्स बनाते-देखते हैं। टिकटॉक का अलागोरिदम बहुत तेज था, जो नए क्रिएटर्स को पुश करता। इंस्टाग्राम में ज्यादा फॉलोअर्स वाले को फायदा। एक रिपोर्ट कहती है कि इंस्टाग्राम पर रीच अच्छी, लेकिन टिकटॉक पर वायरल होना आसान।

मुकाबला कैसा होगा? टिकटॉक के पास ग्लोबल कंटेंट है। लेकिन भारत में इंस्टाग्राम ने लोकल फैचर्स जोड़े। जैसे हिंदी म्यूजिक, इंडियन चैलेंजेस। क्रिएटर्स कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर इडिस से कमाई ज्यादा। टिकटॉक को ये मैच करना होगा। अगर वापस आया तो शुरुआत में उत्साह होगा। पुराने फैस आएंगे। लेकिन लंबे समय

में? इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा मजबूत है। वो रील्स को अपडेट करती रहती है। टिकटॉक को भारतीय यूजर्स के लिए स्पेशल फैचर्स लाने होंगे।

बैलेस्ट व्यू। कुछ कहते हैं टिकटॉक जीतेगा क्योंकि वो ऑरिजिनल है। कोई कहता है इंस्टाग्राम रह जाएगा क्योंकि सुरक्षित। एक सर्वे में पता चला कि भारतीय यूजर्स अब मल्टी-प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते। दोनों चल सकते हैं। लेकिन अगर टिकटॉक आया तो मार्केट शेयर बढ़ेगा। क्रिएटर्स को चुनना पड़ेगा। क्या टिकटॉक इंस्टाग्राम को हराएगा? शायद नहीं आसानी से। पांच साल में रील्स ने मजबूत पकड़ बनाई। गांव से शहर तक। टिकटॉक को नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। सोचिए, क्या आप टिकटॉक पर वापस जाएंगे? या रील्स से खुश हैं?

एक्सप्पर्ट्स कहते हैं कि टिकटॉक की वापसी से इनोवेशन बढ़ेगा। लेकिन सिक्योरिटी चेक जरूरी। एक रिपोर्ट में लिखा, “टिकटॉक की वापसी इंस्टाग्राम और यूट्यूब को चुनौती देगी।” दोनों के बीच लड़ाई यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकती है। ज्यादा ऑफशॉर, बेहतर कंटेंट। लेकिन क्या ये हो पाएगा? समय बताएगा।

क्या हमें टिकटॉक की जरूरत है?

टिकटॉक की वापसी की बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम एक ऐप के लिए सुरक्षा से समझौता करें? या लोकल ऐप्स को बढ़ावा दें? बैन ने दिखाया कि भारत खुद पर निर्भर हो सकता है। अब अगर वापसी हुई तो फायदे-नुकसान दोनों। क्रिएटर्स को मौके मिलेंगे, लेकिन प्राइवेसी का सवाल। सरकार का फैसला महत्वपूर्ण। अभी तो अफवाहें हैं, लेकिन भविष्य में क्या? हमने देखा कि इंटरनेट पर ज्यादातर डेनायल है। लेकिन चर्चा जारी।

सोचिए, डिजिटल दुनिया में बैलेस्ट कैसे रखें? टिकटॉक जैसा ऐप मनोरंजन देता, लेकिन रिस्क भी। भारत बढ़ रहा है, टेक में मजबूत। क्या हम विदेशी ऐप्स पर निर्भर रहें या अपने बनाएं? ये लेख आपको सोचने का मौका देता है। जानकारी ताजा है, लेकिन बदल सकती है। रखिए नजर।



प्रभु कृपा दुर्दिवारण समाप्ति

BY

**Arihanta
Industries**

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML



15 ML



**ULTIMATE
HAIR
SOLUTION**

NO ARTIFICIAL
COLOR
FRAGRANCE
CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.



ORDER ONLINE @ :

amazon

arihanta.in